



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2004/अग्रहायण 24, 1926

No. 293]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2004/AGRAHAYANA 24, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2004

अंतिम जांच परिणाम

विषय :—यूरोपीय संघ तथा इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80 जीएसएम एवं उससे अधिक के पेपर एवं पेपर बोर्ड सहित कोटेड पेपर के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच-अंतिम जांच परिणाम।

सं. 14/7/2003-डी जी ए डी.—क. प्रक्रिया :

1. निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :—

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै. बिल्ट ग्राफिक्स पेपर्स लि. का एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यूरोपीय संघ तथा इंडोनेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80 जी एस एम एवं उससे अधिक के पेपर एवं पेपर बोर्ड सहित कोटेड पेपर के पाटन का आरोप लगाया गया था।
- (ii) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पूर्णतः प्रलेखित आवेदन प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों को सूचित किया।

- (iii) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची - I में 80 जी एस एम एवं उससे अधिक के पेपर एवं पेपर बोर्ड सहित कोटेड पेपर के आयातों के बारे में 17 जून, 2003 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ।
- (iv) प्राधिकारी ने उक्त सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, उद्योग एसोसिएशनों और शिकायतकर्ता को भेजी और उन्हें लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।
- (v) उपर्युक्त नियम 6 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के अनुसार प्राधिकारी ने आवेदन की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों को उपलब्ध कराई । प्राधिकारी ने संगत सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों तथा भारत के आयातकों को प्रश्नावलियां भेजीं । मै. सप्पी यूरोप, ब्रूशेल्स यूरोपीय संघ, और मै. पिन्डो डेली (पी डी) तथा सिनार मैस ग्रुप की मै.जीवी कीमियां (टी के), इंडोनेशिया ने पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत करके आवेदन का उत्तर दिया और निर्यातक प्रश्नावली की परिशिष्टें प्रस्तुत कीं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के सत्यापन का प्रस्ताव भी किया । मै. स्टोरा एन्सो, मै. एम-रियल कार्पोरेशन तथा मै. यू पी एम, ई यू ने भी कुछ सूचना प्रस्तुत की । तथापि, चूंकि उनकी सूचना को काफी दोषपूर्ण माना गया था, इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन प्राधिकारी ने नहीं किया तथा उन्हें संबद्ध जांच में असहयोगी माना गया है ।
- (vi) जांच की शुरुआत के बारे में नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों को भी सूचित किया गया और उनसे यह अनुरोध

किया गया कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें ।

- (vii) अनेक आयातकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं । कुछ आयातकों ने निर्यातक प्रश्नावली में निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं । तथापि, अनंक आयातकों प्रयोक्ताओं ने ऐसे तर्क दिए हैं जिन्हें जांच के लिए संगत पाई गई सीमा तक विश्लेषित किया गया है । जिन आयातकों और प्रयोक्ताओं के विचारों को ध्यान में रखा गया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं ।

प्रयोक्ताओं और आयातकों के नाम:

1. ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ मास्टर प्रिन्टर्स, नई दिल्ली ।
2. ऑल इंडिया पेपर कोटर्स एसोसिएशन, मुंबई ।
3. आई टी सी भद्राचलम पेपर बोर्ड लि., आंध्र प्रदेश ।
4. श्री कृष्णा पेपर मिल्स, नई दिल्ली ।
5. प्रगति आफसेट प्रा.लि., हैदराबाद ।
6. अजन्ता आफसेट, नई दिल्ली ।
7. इंडिया टुडे, नई दिल्ली ।
8. थामसन प्रैस, फरीदाबाद ।
9. अंकित पैकेजिंग लि., हैदराबाद ।
10. पीताम्बर कोटेड पेपर्स, नई दिल्ली ।
11. हीरो पेपर कंपनी, मुंबई ।
12. रोलाटेनर्स, फरीदाबाद ।
13. कास्मोग्राफिक्स, मुंबई ।

14. लक्ष्मी ट्रेडर्स, कोलकाता ।
15. आई टी सी लि., कोलकाता ।
16. गणपति एन्टरप्राइजेज ।
17. श्याम ट्रेडर्स, दिल्ली ।
18. सुमत प्रसाद एंड संस, दिल्ली ।
19. इन्दू मार्केटिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली ।

निर्यातक:

1. मै. मेयर- मेनहॉफ-कॉर्टन, आस्ट्रिया ।
2. मै. एम-रियल कार्पोरेशन, फिनलैंड ।
3. मै. स्टोरा एन्सो फाइन पेपर, नीदरलैंड ।
4. मै. यू पी एम-किमेने कार्पोरेशन, फिनलैंड ।
5. मै. सप्पी फाइन पेपर यूरोप, बेल्जियम ।
6. मै. एशिया पल्प एंड पेपर, इंडोनेशिया ।
7. मै. पी टी पिन्डो डेली, इंडोनेशिया ।
8. मै. पी टी जी वी कीमियां, इंडोनेशिया ।
9. मै. प्रब्रिक कर्टास, इंडोनेशिया ।

उनके विचार अनिवार्यतः आधार संबंधी मुद्दे, घरेलू उद्योग, विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित हैं । उनके तर्कों को संगत शीर्षों में विश्लेषित किया गया है तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षों के दावों के बारे में प्राधिकारी का निर्धारण उन्हीं शीर्षों में दिया गया है ।

- (viii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश अपने पास रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों की जांच हेतु खुला रखा ।
- (ix) *** से इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पता चलता है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।
- (x) पाटन एवं क्षति की जांच में 1 जनवरी, 2002 से 31 दिसंबर, 2002 की अवधि शामिल है (जिसे जांच अवधि भी कहा गया है) । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में रुझानों की जांच में 1 जनवरी, 2000 से जांच अवधि की समाप्ति तक की अवधि शामिल है (जिसे जांचाधीन अवधि अथवा क्षति अवधि भी कहा गया है) । आयात संबंधी आंकड़ों की जांच आई बी आई एस, मुंबई, डी जी सी आई एस के आंकड़ों से तथा आयातकों एवं निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की दृष्टि से की गई है । तथापि, डी जी सी आई एस एवं आई बी आई एस के सौदेवार आंकड़ों सहित समूचे आंकड़ों की जांच करने के बाद निर्यातकों, आयातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं आई बी आई एस (इंटरनेशनल बिजनेस इन्फारमेशन सिस्टम), मुंबई के सौदेवार आंकड़ों पर विश्वास करना उचित समझा गया था क्योंकि डी जी सी आई एस के आंकड़ों से संबद्ध वस्तु के बारे में अनन्य वर्गीकरण का पता नहीं चलता है ।
- (xi) प्राधिकारी ने 4 सितंबर, 2003 को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पार्टियों को अवसर प्रदान किया । मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाली पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने के लिए कहा गया था ।

प्राधिकारी ने घरेलू सत्यापन एवं निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन किया । प्राधिकारी ने पॉटन के निर्धारण एवं क्षति के बारे में अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई समस्त सूचना मांगी और उसका सत्यापन किया । प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग का मौके पर सत्यापन किया । प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातकों अर्थात् मै. सिनॉर मैस ग्रुप, इंडोनेशिया और मै. सप्पी यूरोप, ब्रुशेल्स द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का मौके पर सत्यापन भी किया और उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन किया ।

- (xii) उत्पादन की सर्वोत्तम लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत निकालने के लिए सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के आधार पर तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का भी विश्लेषण किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा । उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार का 29 नवंबर, 2004 को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को खुलासा किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों जिन्हें जांच से संगत माना गया था, पर अंतिम जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद:

2. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में किए गए उल्लेख के अनुसार वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 80 जीएसएम और उससे अधिक के पेपर एवं पेपर बोर्ड

सहित कोटेड पेपर है । विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सीमाशुल्क शीर्ष 4810 के अंतर्गत वर्गीकृत है ।

3. कुछ हितबद्ध पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद में मुद्रण, लेखन और ग्राफिक्स प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त पेपरों से भिन्न कोटेड पेपर भी आते हैं क्योंकि जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद से सीमाशुल्क शीर्ष 4810 का पता चलता है । यह भी तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद में जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित तथा आवेदन में उल्लिखित विवरण से भिन्न अलग-अलग प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त पैकेजिंग बोर्डों तथा अन्य कोटेड बोर्डों सहित सभी प्रकार के कोटेड पेपर शामिल हैं । कुछ हितबद्ध पार्टियों ने इस आशय का तर्क भी दिया है कि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का उचित चयन किया है भले ही उसकी विनिर्माण प्रक्रिया कुछ भी हो जिसके बारे में आवेदन ने अपने आवेदन में दावा किया था । प्राधिकारी ने इन सभी तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच की है । यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी जांच विचाराधीन उत्पाद के वर्णन के आधार पर की जाती है न कि उसके टैरिफ वर्गीकरण के आधार पर । तथापि, जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में इस बात का विशिष्ट उल्लेख किया गया है कि सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संदर्भ को आसान बनाने तथा आयात संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए होते हैं और उनका विचाराधीन उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

4. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में यह उल्लेख किया है कि 80 जीएसएम तथा उससे अधिक के पेपर और पेपर बोर्ड सहित कोटेड पेपरों का उत्पादन विभिन्न

पिगमेंट, बाइंडर्स आदि सहित रसायनों के मिश्रण वाली पतली फिल्म को प्रयोग में लाकर किया जाता है । उन्होंने यह भी कहा था कि कोटिंग प्रक्रिया का उपयोग प्रिंट ग्रॉस में सुधार करने तथा प्रिंटिंग पेपरों को मुलायम बनाए रखने के लिए किया जाता है । कोटिंग की प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रक्रियाओं अर्थात् एयर नाइफ कोटिंग तथा ब्लेड कोटिंग द्वारा की जाती है । आवेदन द्वारा ब्लेड कोटिंग प्रौद्योगिकी को अपनाकर कोटेड पेपर का उत्पादन किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इस प्रकार से उत्पादित तैयार पेपर में मुलायमपन, परिष्करण का अपेक्षित स्तर है और वह एयर नाइफ कोटिंग तकनीक द्वारा उत्पादित कोटेड पेपर की तुलना में कोटिंग और बेहतर मुद्रण योग्यता के अनुरूप है । ब्लेड कोटेड प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कोटेड पेपर का उच्च आई जी टी मूल्य होता है जिसका उपयोग उच्च गति से मुद्रण में किया जा सकता है । दूसरी ओर एयर नाइफ प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कोटेड पेपर का कम आई जी टी मूल्य होता है जिस पर उसी मुद्रण गति से मुद्रण नहीं किया जा सकता । घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से आयातित पेपर का उत्पादन उच्च आई जी टी मूल्य वाली ब्लेड कोटेड प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है और इसलिए वह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पेपर का प्रत्यक्ष प्रतिस्थापनीय है । उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि वर्तमान याचिका ब्लेड कोटेड तकनीक से उत्पादित कोटेड पेपर के विरुद्ध ही दायर की गई है क्योंकि ऐसे उत्पाद संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों से सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं ।

5. अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि किसी पाटनरोधी जांच में विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया को एक कारक के रूप में नहीं लिया जा सकता । प्राधिकारी ने निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की

सावधानीपूर्वक जांच की है । विनिर्माण प्रक्रिया एवं संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के तकनीकी ब्यौरों तथा घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों के ब्यौरों का प्राधिकारी ने वास्तविक सत्यापन भी किया था । विस्तृत तकनीकी विनिर्देशनों तथा ब्लेड कोटेड एवं एयर नाइफ पेपरों के बीच तकनीकी और वाणिज्यिक अंतरों की भी जांच की गई है । घरेलू उद्योग एवं संबद्ध देशों के सहयोगी निर्यातकों, जिनके परिसरों के साथ-साथ उनकी फैक्टरियों तथा सूचना का सत्यापन दलों द्वारा वास्तविक सत्यापन किया गया था, सहित सभी हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त उपर्युक्त निर्विष्टियों के आधार पर प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से आयातित कोटेड पेपर का निर्माण मुख्यतः ब्लेड कोटिंग प्रौद्योगिकी के जरिए किया जाता है क्योंकि हाल के वर्षों में एयर नाइफ कोटिंग तकनीकें प्रचलन में नहीं हैं (इनका स्थान ब्लेड कोटेड प्रक्रिया न ले लिया है) । तथापि, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के बाद में प्रस्तुत इन विचारों से सहमत नहीं हैं कि उत्पाद के क्षेत्र को ब्लेड प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित उत्पाद तक ही सीमित किया जाना चाहिए क्योंकि वह नोट करते हैं कि उत्पाद के क्षेत्र को कोटिंग प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं किया जा सकता भले ही उक्त कोटिंग प्रक्रिया से उत्पाद को ग्लोसिनेस, आईजीटी मूल्य एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता जैसे गुणधर्मों के संबंध में कुछ लाभ मिलता हो । प्रकटन विवरण के बाद विभिन्न हितबद्ध पार्टियों ने प्रकटन विवरण में उल्लिखित अपने विचारों को दोहराया है और कोई नया अनुरोध/तथ्य प्राधिकारी की जानकारी में नहीं लाया गया है । उपर्युक्त सभी कारकों पर विचार करते हुए प्राधिकारी जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित "80 जीएसएम और उससे अधिक के पेपर एवं पेपर बोर्ड सहित कोटेड पेपर" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु ही कहा गया है) को ही विद्याराधीन उत्पाद मानते हैं । संबद्ध वस्तु में 80 जीएसएम से कम के कोटेड पेपर, (जिसे आम तौर पर कम वजनी कोटेड पेपर के

रूप में जाना जाता है) ग्लैज्ड अखबारी कागज तथा सभी प्रकार के अनकोटेड पेपर शामिल नहीं हैं ।

समान वस्तु:

6. आवेदक ने दावा किया है कि नियम 2 (घ) के अंतर्गत "समान वस्तु" को ऐसी किसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु से हर तरह से समान अथवा समरूप है । उनका यह तर्क है कि ऐसी किसी वस्तु के अभाव में ही ऐसी किसी अन्य वस्तु को "समान वस्तु" माना जा सकता है जो उसके समरूप न हो किन्तु उसकी विशेषताएं पाटित वस्तु से अत्यंत मेल खाती हों । याचिकाकर्ताओं के अनुसार वर्तमान मामले में ब्लेड कोटेड पेपर का पाटन किया जा रहा है क्योंकि यह कोटेड पेपर की एकमात्र वह किस्म है जिसका उत्पादन विदेशों में किया जाता है जबकि एयर नाइफ पेपर की मात्रा बहुत ही कम अथवा नगण्य होती है । यह भी अनुरोध किया गया था कि विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर के अलावा परिणामी अंतिम उत्पाद में एक-दूसरे से पर्याप्ततः विभिन्न विशेषताएं हैं । अतः उन्होंने अनुरोध किया कि पाटनरोधी नियमों के अनुसार "घरेलू उद्योग" की परिभाषा में एयरनाइफ पेपर के उत्पादकों को शामिल करना कानूनी दृष्टि से अनुमत्य नहीं होगा । उनका यह दावा है कि उनका उत्पादन "सामान्य वस्तु" अर्थात् 80 जीएसएम और उससे अधिक के पेपर तथा पेपर बोर्ड सहित ब्लेड कोटिंग किस्म के कोटेड पेपर के घरेलू उत्पादन का 95% से अधिक बनता है । अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने बिड़ला पैरीक्लास बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2000(16)ईएलटी 336(ट्रिब्यूनल) में सूचित मामले में पारित सैस्टेड के निर्णय पर भरोसा व्यक्त किया है जिसमें उसने यह निर्णय दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को

परिभाषा की पहली अपेक्षा में यथापरिकल्पित किसी समनुरूप वस्तु के अभाव में ही "समान वस्तु" की परिभाषा की दूसरी अपेक्षा का सहारा लेने की अनुमति है ।

7. कुछ आयातकों और निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि एयरनाइफ कोटिंग तथा ब्लेड कोटेड प्रौद्योगिकी के जरिए उत्पादित कोटेड पेपर को निश्चित रूप से समान वस्तु के रूप में समूहबद्ध किया जा सकता है । यह तर्क दिया गया है कि "समान वस्तु" के निर्धारण हेतु विनिर्माण की प्रक्रिया संगत नहीं है । संबंधित निर्यातक ने चीन से 3,4,5-टी एम बी ए, 8 एच क्यू तथा मैग्नेशियम के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णयों का उल्लेख किया है । अनुरोध है कि इन सभी मामलों में उत्पादन प्रक्रिया को "समान वस्तु" के निर्धारण हेतु संगत नहीं माना गया था । मै. एम-रियल ने घरेलू उद्योग की ओर से अथवा उसके लिए पाट रोधी आवेदन दायर करने के बारे में याचिकाकर्ताओं के आधार के संदर्भ में इसी प्रकार के तर्क दिए हैं ।

प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है और उन्होंने घरेलू उद्योग के अनुरोधों की भी जांच की है ।

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(घ) में समान वस्तु को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

"(घ) "समान वस्तु" से तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु से है जो भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु से हर प्रकार से समान अथवा समनुरूप है अथवा ऐसी किसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु से है जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है तथापि, उसकी विशेषताएं जांचाधीन वस्तु की विशेषताओं से अत्यधिक मिलती-जुलती हैं ।"

9. उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि कोई उत्पाद "समान वस्तु" तब माना जाता है जब वह जांचाधीन उत्पाद के हर प्रकार से समान अथवा समनुरूप हो । ऐसी किसी वस्तु के अभाव में ही प्राधिकारी को "समान वस्तु" की परिभाषा की दूसरी अपेक्षा का सहारा लेने की अनुमति होगी । यह तर्क दिया गया है कि निर्यातकों द्वारा उल्लिखित निर्णय इन मामलों में संगत नहीं हो सकते क्योंकि प्राधिकारी ने परिभाषा की दूसरी अपेक्षा का उस स्थिति में सहारा लिया है जब घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य वस्तु का उत्पादन "सामान्य वस्तु" की परिभाषा की पहली अपेक्षा के रूप में परिकल्पित घरेलू उद्योग द्वारा विधिसंगत ढंग से नहीं किया गया हो । प्राधिकारी ने निर्यातकों के इस कथन की जांच की थी कि एयर नाइफ प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पेपर को "समान वस्तु" में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था । अपनी उत्पादन क्षमताओं सहित नाम और पते देते हुए निर्यातकों के अभ्यावेदन के बाद प्राधिकारी ने दूसरे उत्पादकों द्वारा अन्य प्रक्रियाओं के जरिए निर्मित कोटेड पेपर के उत्पादन के ब्यौरे मांगे थे जैसा कि अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा जिनमें मुख्यतः निर्यातक और आयातक शामिल थे, द्वारा आरोप लगाया गया था । यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पाद जैसे उत्पाद के तथाकथित अन्य उत्पादकों को उनके उत्पादन, क्षमता और इस तथ्य के बारे में सूचना देने के लिए अनेक अवसर दिए गए थे कि क्या वे अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार संबद्ध वस्तु के समान वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं । तथापि, यह नोट किया जाता है कि आरोपित अन्य उत्पादकों ने जांचाधीन अवधि के लिए अपने संयंत्र के उत्पादन संबंधी ब्यौरों को छोड़कर प्रपत्र में यथाअपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की । चूंकि आरोपित अन्य

उत्पादकों से उत्पादन संबंधी व्यौरों को छोड़कर कोई सूचना नहीं मिली है इसलिए प्राधिकारी ने अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कार्रवाई की है ।

10. समान वस्तु के निर्धारण हेतु प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या विभिन्न प्रकार उत्पाद विनिर्देशनों, भौतिक एवं तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, संयंत्र एवं उपकरण, कार्य एवं उपयोग, उनकी प्रतिस्थापनीयता, टैरिफ वर्गीकरण तथा उपभोक्ता अवधारणा जैसे मानदंडों के संबंध में तुलनीय है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु की तकनीकी विशेषता संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान/तुलनीय है और दोनों भौतिक, रासायनिक गुणधर्मों तथा उसके उपयोग के संबंध में प्रतिस्थापनीयता के अनुसार तुलनीय है । प्रकटन विवरण के बाद विभिन्न हितबद्ध पार्टियों ने प्रकटन विवरण में उल्लिखित अपने विचारों को दोहराया है और कोई नया अनुरोध/तथ्य प्राधिकारी की जानकारी में नहीं लाया गया है ।

11. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है ।

घरेलू उद्योग का आधार:

12. जांच की शुरुआत के बाद कुछ निर्यातकों और आयातकों ने यह तर्क दिया है कि आवेदक के पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवेदन दायर करने का आधार नहीं है । उनके तर्क में इस बात पर जोर दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा "समान वस्तु" का उत्पादन 25% की न्यूनतम सीमा से कम

बनता है । अपने तर्क के समर्थन में ई यू के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों में से एक निर्यातक मै. एम-रियल ने जाक्को पोयरी की एक रिपोर्ट पर भरोसा व्यक्त किया है जिसे उनके कहने पर जांच की शुरुआत के बाद प्राप्त किया गया है ।

13. यह नोट किया जाता है कि अपने आवेदन में याचिकाकर्ताओं ने यह उल्लेख किया था कि उनका उत्पादन देश में "समान वस्तु" के उत्पादन का 95% से अधिक बनता है । प्राधिकारी ने पॉटनरोधी नियमावली के नियम 5(2) के अंतर्गत अपने दायित्व के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्पादन संबंधी ब्यौरों की जांच की थी और मै. बिल्ट ग्राफिक्स पेपर को पॉटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवेदन दायर करने के लिए अपेक्षित आधार रखने वाला माना था क्योंकि उनका उत्पादन नियम 2(घ) के साथ पठित घरेलू उद्योग बनने के लिए नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है । जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के बाद ई यू के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों में से एक निर्यातक मै. एम-रियल ने आवेदक की घरेलू उद्योग संबंधी स्थिति को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसमें उनकी दलील को वापस लिया गया माना गया था । तथापि, सार्वजनिक सुनवाई, जिसमें संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधियों सहित अधिकांश हितबद्ध पार्टियां उपस्थित हुई थीं, में और सार्वजनिक सुनवाई के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष दिए गए लिखित अनुरोधों में प्राधिकारी के समक्ष यह दलील दी गई थी कि वह संबद्ध वस्तु के अन्य आरोपित उत्पादकों से कहें और उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार आवेदक के आधार की पुनः जांच करें । यद्यपि उन्हें यह बता दिया गया था कि संबंधित मंत्रालय को एक पत्र पहले ही भेज दिया गया है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा है । तथापि, अन्य हितबद्ध पार्टियों ने यह अनुरोध किया कि प्राधिकारी को संबंधित उत्पाद के तथाकथित अन्य उत्पादकों से

सक्रियतापूर्वक पूछताछ करनी चाहिए ताकि जांच में कार्रवाई आगे बढ़ाने से पूर्व प्राधिकारी घरेलू उद्योग के आधार के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकें । उन्होंने आधार संबंधी मुद्दे की पुनः जांच होने तक जांच की कार्रवाई आगे न बढ़ाने के बारे में प्राधिकारी से अनुरोध भी किया ।

14. घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के आधार का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ यह देखना होता है कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं । संगत नियमों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है ।

"नियम 5(3): निर्दिष्ट प्राधिकारी उपनियम (1) के अंतर्गत किसी आवेदन के अनुसरण में कोई जांच तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक कि -

(क) समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा आवेदन के बारे में व्यक्त समर्थन अथवा उसके विरोध के स्तर की जांच के आधार पर वह यह निर्धारित न कर ले कि उक्त आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर किया गया है :

किन्तु उस स्थिति में कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी यदि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25% से कम बनता हो, और

(ख) वह आवेदन में उपलब्ध साक्ष्य की यथा तथ्यता और पर्याप्तता की जांच न कर ले और निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य होने के प्रति स्वयं को संतुष्ट न कर ले -

- (i) पाटन,
- (ii) क्षति, जहां लागू हो, और
- (iii) जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए ऐसे पाटित आयातों और आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, जहां लागू हो ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ आवेदन को उस स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया माना जाएगा यदि उसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया हो जिनका सामूहिक उत्पादन उक्त आवेदन के प्रति समर्थन अथवा विरोध, जैसा भी मामला हो, व्यक्त करने वाले घरेलू उद्योग के उक्त भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50% से अधिक बनता हो ।"

15. उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राधिकारी के लिए कुल उत्पादन और जहां तक "समान वस्तु" का संबंध है, केवल याचिकाकर्ताओं के उत्पादन पर विचार करना अपेक्षित है । पूर्ववर्ती पैराग्राफों में अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच जारी रखते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कुछेक निर्यातकों और आयातकों द्वारा किए गए अनुरोध त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे अनेक पेपरों को शामिल किया है जो न तो विचाराधीन उत्पाद हैं और न ही "समान वस्तु" हैं । जहां तक निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लागू की गई जांच का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ताओं का

उत्पादन देश में ब्लेड कोटेड पेपर ("समान वस्तु") के उत्पादन का 95% से अधिक बनता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अत्यधिक सावधानी के रूप में प्राधिकारी ने पेपर एवं पेपर बोर्ड सहित सभी कोटेड पेपरों के आंकड़े भी प्राप्त किए भले ही जांच की शुरुआत से पूर्व कोटिंग की प्रक्रिया कुछ भी रही हो। प्राधिकारी ने यह पाया था कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन (प्रक्रिया पर ध्यान न देते हुए पेपर और पेपर बोर्ड सहित कोटेड पेपर के बारे में) 50% से अधिक बनता है। इस प्रकार उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी ने जांच की थी और स्वयं को इस बात से संतुष्ट किया था कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) में निर्धारित आधार संबंधी मानदंड को पूरा करते हैं।

16. सार्वजनिक सुनवाई के बाद प्राधिकारी ने सी पी पी आर आई से सूचना भी प्राप्त की जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन जांच अवधि के दौरान 252728 मी.ट. रहा था। वस्तुतः जैको पोयरी के 2 सितंबर, 2003 के पत्र में भी यह उल्लेख किया गया है कि कोटेड पेपर (एयर नाइफ तथा ब्लेड कोटेड प्रौद्योगिकी दोनों से) का कुल उत्पादन 240000 मी.ट. हुआ है। तथापि, संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस दृष्टि से अपूर्ण है कि उसमें सभी हितबद्ध पार्टियों द्वारा की गई जांच पड़तालों का निपटान नहीं किया गया है। तथापि, प्राधिकारी द्वारा संबंधित उत्पाद के आरोपित सभी उत्पादकों को लिखे गए पत्रों के उत्तर में उनकी एसोसिएशन अर्थात् मै. ऑल इंडिया पेपर कोटर्स एसोसिएशन ने प्राधिकारी को लिखे अपने पत्र में संबद्ध वस्तु का कुल उत्पादन 156886 मी.ट. बताया है और उन्होंने ई यू एवं इंडोनेशिया से पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए मै. बिल्ट ग्राफिक्स पेपर्स लि. द्वारा दायर आवेदन का समर्थन किया है। उत्पादन संबंधी इस आंकड़े से आवेदक नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के

अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग बनता है और इस प्रकार उनके पास पाटनरोधी विनियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवेदन दायर करने का आधार है। प्रकटन विवरणों के तर्क दिए गए हैं कि मै. बिल्ट ग्राफिक्स लि. का कोई कानूनी अर्थ नहीं है क्योंकि 2002 से इसने मै. वल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि. में विलय के बाद अपना अस्तित्व खो दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में मूल आवेदक मै. बिल्ट ग्राफिक्स पेपर लि. ने आमेलन स्कीम तथा कंपनी अधिनियम की शर्तों के अनुसार दोनों के बीच हुई व्यवस्था के तहत वल्लारपुर इंडस्ट्रीज के साथ औपचारिक विलय किया है। यह स्कीम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 27 मार्च, 2003 को और मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा 10 अप्रैल, 2003 को अनुमोदित की गई थी। सांविधिक विवरणी आर ओ सी मुंबई में 29 मई, 2003 को तथा 19 जून, 2003 को प्रस्तुत की गई थी। बाद में घरेलू उद्योग ने आमेलन स्कीम (पूर्ववर्ती तारीख से प्रभावी) के साथ इन आदेशों की प्रतियां प्राधिकारी को प्रस्तुत की थी। यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए कोई पाटनरोधी आवेदन दायर करने के बारे में आवेदक का आधार जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर होता है। अतः उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर परवर्ती आमेलन से घरेलू उद्योग के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां तक आई टी सी लि. को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग लखने के बारे में हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का संबंध है, यह बताया जाता है कि प्राधिकारी को अनेक अनुस्मारकों के बावजूद उनके उत्पादन संबंधी ब्यौरों अथवा निर्यातक के साथ उनकी संबद्धता के बारे में कोई उत्तर नहीं मिला है।

17. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अंतर्गत जांच अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन

के एक बड़े हिस्से का उत्पादन करके "घरेलू उद्योग" की पात्रता पूरी करता है और वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) में यथा परिकल्पित आधार संबंधी मानदंड की पूर्ति करता है।

पद्धति और पाटन का निर्धारण

च. पाटन

18. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1) के अंतर्गत समान वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

1. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित उक्त वस्तु का तुलनीय मूल्य जब वह निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में खपत के लिए उद्दिष्ट हो; अथवा
2. जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब बाजार की विशेष स्थिति अथवा निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा रहने की वजह से ऐसी बिक्रियों की उचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

क. उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य जब उसका निर्यात निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा किसी उपयुक्त तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

ख. उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य खर्चों के लिए तथा लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ मूलता के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

किन्तु जहां मूलता के देश से भिन्न किसी देश से उक्त वस्तु का आयात किया गया हो अथवा जहां निर्यात के देश से होकर उक्त वस्तु को केवल यानांतरित किया गया हो अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में न किया गया हो अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय मूल्य न हो वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

19. प्राधिकारी ने धारा 9 क (i)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं । केवल 3 उत्पादकों अर्थात् मै. सप्पी यूरोप (बुशेल्स), ई.यू. और मै. टी.के. तथा मै. पी.डी. (इंडोनेशिया) ने निर्यातक एवं निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार अपेक्षित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर दिया है ।

च.1 ई.यू.

(क) सहयोग

20. मै. सप्पी यूरोप, ई.यू. ने निर्यातक प्रश्नावली में उल्लिखित विभिन्न परिशिष्टों के बारे में पर्याप्त सूचना देकर निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है । उन्होंने उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के सत्यापन का भी प्रस्ताव किया और प्राधिकारी ने उत्पादकों एवं निर्यातक के परिसरों का मौके पर निरीक्षण करने के बाद आंकड़ों का

सत्यापन किया है । अन्य निर्यातकों अर्थात् मै. स्टोरा एन्सो और मै. एम. रियल ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर दिया है और सार्वजनिक सुनवाई में भी उपस्थित हुए हैं किन्तु उन्होंने प्राधिकारी द्वारा निर्यातक प्रश्नावली में यथानिर्धारित प्रपत्र में और ढंग से मांगी गई सूचना नहीं भेजी है । प्राधिकारी स्मरण करते हैं कि जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की तारीख से 40 दिन की सामान्य समयावधि के अलावा सूचना प्रस्तुत करने के लिए इन निर्यातकों को आगे और समय दिया गया था किन्तु उन्होंने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करके प्राधिकारी के उत्तर का जवाब नहीं दिया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा निर्यातक प्रश्नावली में यथा निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करने और अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के बारे में इन कंपनियों को स्मरण कराया गया और इन्हें इस बात का भी स्मरण कराया गया कि यदि उचित समय के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा जांच की शुरूआत हेतु आवेदन में निहित तथ्यों सहित उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. सप्पी यूरोप (ई.यू.) को छोड़कर किसी भी निर्यातक और उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली में अपेक्षित प्रपत्र में और ढंग से परिशिष्टवार सूचना मांगते हुए प्राधिकारी के पत्र का उत्तर नहीं दिया है । चूंकि इंडोनेशिया के निर्यातकों अर्थात् मै. पी.डी. और मै. पी.के. ने आंशिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिनका प्राधिकारी ने सत्यापन किया है इसलिए उन्हें आंशिक सहयोगी माना जा रहा है । निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत न किए जाने को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटनरोधी करार एवं पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर शेष उत्पादकों और निर्यातकों को असहयोगी मानते हैं ।

(ख) सप्पी यूरोप, बूशेल्स के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

21. (i) सप्पी यूरोप, बेल्जियम ने निर्यातक प्रश्नावली का विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया है । उन्होंने प्रश्नावली के सभी खंडों और नए प्रपत्र के अनुसार परिशिष्ट 1, 2, 2क, 2ख, 3, 3क, 3ख, 4, 5, 6, 7, 8क, 8ख और 9 से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है । सप्पी ने वित्त वर्ष जांच अवधि और उससे पूर्व के 2 वर्षों के लिए विस्तृत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत किए हैं । उत्तर के अवलोकन से यह पता चलता है कि सप्पी यूरोप की 7 संबंधित कंपनियां हैं जो यूरोप में संबंधित उत्पाद का उत्पादन करती हैं ।
- (ii) यूरोप में घरेलू बिक्रियां सप्पी यूरोप एस.ए. (जिसे आगे सप्पी यूरोप कहा गया है) द्वारा संचालित की जाती हैं । सप्पी यूरोप, यूरोप में अपने ग्राहकों से आर्डर प्राप्त करता है । आर्डर उत्पाद, डिलीवरी कार्यक्रम, उपलब्धता, डिलीवरी स्थल आदि के अनुसार सातों उत्पादक उत्पादनकर्ता मिलों में से किसी एक के पास भेज दिए जाते हैं । संबंधित मिल ग्राहक को वस्तु की आपूर्ति करता है और आंतरिक बीजक सप्पी, यूरोप को जारी कर देता है । सप्पी यूरोप ग्राहक को बीजक जारी करता है । कुल मिलाकर सप्पी यूरोप संबंधित मिलों के एजेंट के रूप में कार्य करता है ।
- (iii) भारत के लिए निर्यात बिक्रियां एक अन्य संबद्ध कंपनी मै. सप्पी पेपर होल्लिंग जी एम बी एच की हांगकांग शाखा द्वारा संचालित की जाती हैं । सप्पी पेपर होल्लिंग जी एम बी एच की हांगकांग शाखा ग्राहकों से आर्डर प्राप्त करती है और उन्हें संबंधित मिलों के पास भेज देती है । उक्त मिल भारत में ग्राहकों

को माल सीधे भेज देती है और सप्पी पेपर होलिंग, हांगकांग ब्रांच को आंतरिक बीजक जारी कर देती है जो बाद में भारत में स्थित ग्राहकों को बीजक जारी करती है ।

- (iv) सप्पी ने सप्पी यूरोप एस ए द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों के बीजकों और सप्पी होलिंग ए जी, हांगकांग द्वारा की गई निर्यात बिक्रियों के बीजकों की नमूना प्रतियां प्रस्तुत की हैं । घरेलू बिक्री के दस्तावेजों में ऑर्डर पुष्टिकरण, बीजक और भार सूची शामिल हैं । निर्यात बिक्री के दस्तावेजों में आर्डर पुष्टिकरण, वाणिज्यिक बीजक, भार सूची, मात्रा/गुणवत्ता, जांच प्रमाण-पत्र, समुद्री बीमा प्रमाण-पत्र, नौवहन बिल और मूलता प्रमाण पत्र शामिल हैं ।
- (v) **परिशिष्ट-1:** ई.यू. में घरेलू बाजारगत बिक्रियों से संबंधित सूचना में *** रिकॉर्ड निहित हैं । चूंकि किसी एम.एस. एक्सल फाइल में अधिकतम 65, 536 रिकॉर्डों को हैंडिल किया जा सकता है, अतः यह परिशिष्ट एम.एस. एक्सल के लिए काफी लंबी है । अतः सप्पी ने एम.एस. एक्सिस फार्मेट में फाइल प्रस्तुत की है इस परिशिष्ट का सारांश एम एस एक्सिस का उपयोग करते हुए तैयार किया गया था । सारांश रिपोर्ट में घरेलू बिक्रियों के उत्पाद कोड-वार ब्यौरे दिए गए हैं । सारांश रिपोर्ट के प्रमुख मानदंड गोपनीय संलग्नकों में दिए गए हैं ।
- (vi) इसी प्रकार सप्पी ने **परिशिष्ट-2:** एम एस एक्सिस फार्मेट में भारत को निर्यातों के बारे में सप्पी ने सूचना प्रस्तुत की है । सारांश रिपोर्ट एम एस

एक्सिस का उपयोग करते हुए तैयार की गई थी । फाइल के प्रमुख मानदंड निम्नानुसार हैं :-

- I. भारत को निर्यात बिक्रियों में *** रिकॉर्ड शामिल हैं;
 - II. भारत को निर्यातित सामग्री *** अलग-अलग उत्पाद कोडों के अंतर्गत आती हैं;
 - III. भारत को निर्यातित कुल मात्रा *** मी.टन थी ।
 - IV. निवल बीजक मूल्य *** यूरो था
 - V. कारखाना द्वार पर प्राप्ति *** यूरो थी
 - VI. भारत को भारत औसत कारखाना निर्यात कीमत *** यूरो प्रति मी. टन थी ।
- (vii.) उपर्युक्त दोनों सारांश रिपोर्टों को "सप्पी एनलेसिस.एक्स एल एस" नामक एम एस एक्सल फाइल में परिवर्तित किया गया था । अन्य सभी परिशिष्टें एम एस एक्सल फॉर्मेट में दी गयी हैं ।
- (viii.) परिशिष्ट- 2 क में घरेलू बिक्री तथा वर्ष 2001, 2002 और सितंबर, 2003 तक भारत को हुई निर्यात बिक्रियों की "मासिक बिक्री पर्यावलोकन" दिया गया है । मासिक बिक्री पर्यावलोकन के अनुसार कुल योग की प्रति जांच परिशिष्ट 1 और 2 में दिए गए ब्यौरों के साथ की गई थी ।
- (ix.) सप्पी ने परिशिष्ट-3 क : भारत को निर्यातों के लिए बिक्री कीमत संरचना प्रस्तुत की है । उन्होंने ऋण लागत, रिबेट, कमीशन, भाड़ा और बीमा के लिए छूट का दावा किया है । कारखाना द्वार पर निवल निर्यात कीमत *** यूरो प्रति मी.टन बनती है । परिशिष्ट-2 ख: घरेलू बिक्रियों के लिए बिक्री कीमत संरचना में सप्पी ने छूट रिबेट कमीशन भाड़ा और बीमा के लिए घरेलू

बिक्रियों में से छूट का दावा किया है । कारखाना द्वार पर घरेलू बिक्री प्राप्ति *** यूरो प्रति मी.टन बनती है । परिशिष्ट 3 क में दर्शायी गयी भारत के लिए कारखाना द्वार पर निवल निर्यात कीमत और परिशिष्ट 3 ख में दर्शायी गई कारखाना द्वार पर घरेलू बिक्री कीमत क्रमशः परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 1 से मूल खाती है ।

- (X) परिशिष्ट 4 में सप्पी ने क्षमता, उत्पादन और सप्पी की बिक्री के समग्र आंकड़े प्रस्तुत किए हैं । परिशिष्ट 5 में सप्पी ने कच्ची सामग्री और पैकेजिंग सामग्री की खपत का विवरण प्रस्तुत किया है । परिशिष्ट 6 में सप्पी ने भारत को निर्यातित तथा यूरोप में बिक्रीत उत्पादों के किस्म-वार आंकड़ों से संबंधित समस्त लागतें प्रस्तुत की हैं ।
- (xi.) परिशिष्ट 7 में सप्पी ने वर्ष 2002 के लिए कंपनी के समग्र प्रचालनों के बारे में आवंटन तथा व्यय के अनुपात जांचाधीन उत्पाद पर लागू शेयर तथा अन्य उत्पादों के लिए लागू शेयर के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं । परिशिष्ट 8 क में सप्पी ने उत्पादों की किस्म के संबंध में भारत को किए गए निर्यातों की फैक्ट्री लागत और लाभों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं जिन्हें भारत को निर्यात किया गया है । इसी प्रकार सप्पी ने परिशिष्ट 8 ख भी प्रस्तुत की है ।
- (xii.) पाटनरोधी नियमावली और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुपालन में ई.यू. घरेलू बाजार में बेचे गए प्रत्येक उत्पाद के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है ।

ऐसे केवल *** उत्पाद-विवरण थे जिनका भारत को निर्यात किया गया था । समस्त *** उत्पाद विवरणों के संबंध में यह पाया गया था कि 20% से कम घरेलू बिक्रियां, उत्पादन लागत से कम कीमत पर की गई थीं । अतः समस्त *** उत्पाद विवरणों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया था ।

(xiii.) इसके अलावा, प्राधिकारी ने भारत को हुई निर्यात बिक्रियों और घरेलू बाजार में उनकी बिक्रियों में समायोजन संबंधी कारकों का भी सत्यापन किया । जहां तक भारत को हुई निर्यात बिक्रियों में समायोजन के कारकों का संबंध है, प्राधिकारी ने उनके रिकार्डों से यह सत्यापन किया कि क्या उनके द्वारा दावा किए गए और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित सभी समायोजनों को निर्यात कीमत में से कम कर दिया गया है ।

(xiv.) पाटन मार्जिन संबंधी आंकलनों को सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के संबंध में निर्यातकों के आंकड़ों का सत्यापन करने के बाद और समस्त समायोजनों का सत्यापन करने के बाद संशोधित किया गया था । सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के निर्धारण से संबंधित आंकलन गोपनीय विवरण में संलग्न है ।

ई.यू. के अन्य निर्यातक

22. चूंकि सहयोगी निर्यातक से भिन्न निर्यातकों से भारत को किए गए निर्यातों की मात्रा समग्र ई.यू. से हुए आयात की कुल मात्रा की तुलना में काफी अधिक थी, इसलिए नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और भारत को उनके निर्यातों के अनुसार निर्यात कीमत लेते हुए शेष निर्यातकों के लिए

अवशिष्ट पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है । प्रकटन विवरण के बाद घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यूरोपीय संघ के अन्य निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार ली जानी चाहिए । प्रकटन विवरण के उत्तर में यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग की क्षति के निर्धारण हेतु निर्यात कीमत को डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । प्राधिकारी ने ई यू के अन्य निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत की गणना के बारे में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों के तर्कों की जांच की है । प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि संबद्ध जांच, जांच अवधि और उससे पूर्व के 2 वर्षों के लिए आई बी आई एस के सौदेवार आंकड़ों से प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए आयात संबंधी आंकड़ों के साथ शुरू की गई थी । आवेदन द्वारा तत्पश्चात् यह तर्क दिया गया था कि चूंकि विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण छः अथवा आठ अंकीय सीमा शुल्क शीर्ष में शामिल नहीं किया गया था और विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए डी जी सी आई एंड एस के संक्षिप्त वर्गीकरण पर भरोसा करना व्यवहार्य नहीं है । जांच की शुरुआत के बाद प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से सौदेवार आंकड़े मांगे थे । तथापि, सौदेवार आंकड़ों की जांच करने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि संबद्ध आयात अनेक वर्गीकरणों में सूचित किए गए हैं और सौदेवार सूचना से लिए गए आंकड़े को विचाराधीन उत्पाद के लिए कम पाया गया था, जब उनकी जांच प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आयातों के वास्तविक आंकड़ों के साथ की गई थी । निदेशालय में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातक अर्थात् मै. सप्पी (यूरोप) और मै. स्टोरा एन्सो द्वारा उनकी निर्यात कीमत निकालने के लिए प्रस्तुत निर्यात संबंधी आंकड़ों को स्वीकार किया है । तथापि, चूंकि केवल मै. सप्पी, यूरोप ने निर्यातक प्रश्नावली में निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से पूर्ण सूचना प्रस्तुत की है, इसलिए उन्हें संबद्ध जांच में सहयोगी निर्यातक

घोषित किया गया है । शेष निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण प्राधिकारी के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार किया गया है ।

टी.के., इंडोनेशिया और पी.डी., इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

23. इस समूह को समग्र रूप से सिनार मैस ग्रुप कहा जाता है । सिनार मैस ग्रुप को बाद में अलग-अलग कारोबारी यूनिटों में विभाजित कर दिया गया था । इनमें से एक कारोबारी यूनिट मै. पी.टी. पैब्रिक कोर्टास जी बी कीमिया टी बी के (कंपनी) है जिसे *** जो कंपनी की प्रमुख शेयरधारी है, द्वारा नियंत्रित किया जाता है । फर्म की दूसरी कारोबारी यूनिट मै. पिंडो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स (कंपनी) है जिसे अप्रत्यक्ष इक्विटी निवेशों के जरिए *** द्वारा नियंत्रित किया जाता है । *** द्वारा *** के प्रमुख शेयर धारित किए जाते हैं जो कि कंपनी के अधिकांश शेयरों को धारण करती है । इन दोनों कंपनियों से पर्याप्त सूचना प्रस्तुत किए जाने के बाद डी जी ए डी की सत्यापन टीम द्वारा सत्यापन दौरा किया गया था । इस बात का सत्यापन किया गया था कि कोटेट पेपर और पेपर बोर्ड के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री लुग्दी है, जिसे कंपनी की सहायक कंपनी द्वारा विनिर्मित किया जाता है और जिसे बाहर से भी प्राप्त किया जाता है । कीमत/अंतरण कीमत अमरीकी डॉलर में तय की जाती हैं । कंपनी ने दावा किया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कीमतें दर्शाती हैं और कच्ची सामग्री की कीमतें दूरवर्ती सौदों पर आधारित होती हैं ।

(i) पी टी पैब्रिक कर्टास जी बी कीमिया टीबीके (टी.के.)

(क) कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण इंडोनेशिया में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (इंडोनेशिया जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं । कंपनी अपनी

रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ मासिक लाभ एवं हानि देखे तथा उत्पादन लागत रिपोर्टें तैयार करती हैं । कंपनी ने अपनी प्रचालन और वित्तीय सूचना प्रणाली के लिए ई आर पी प्रणाली को कार्यान्वित किया है । मै. पी टी पैब्रिक कर्टाज जी बी कीमिया (टी के) ने जांच दल को उत्पादन लागत संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं । कंपनी की रिपोर्ट वर्ष कलेंडर वर्ष है जो जांच अवधि से मेल खाती है । परिशिष्ट 7 और 8 में प्रस्तुत सूचना को प्रकटिसकर्ता लेखाकार द्वारा सत्यापित की जानी अपेक्षित है जिसे कंपनी ने उपलब्ध नहीं कराया है । यह सत्यापित किया गया था कि जांच अवधि के दौरान कोटेड पेपर और पेपर बोर्ड का कुल उत्पादन *** (क्षमता उपयोग***)

हुआ था । जांच अवधि के दौरान कुल बिक्री *** की हुई थी । कंपनी ने परिशिष्ट 7 और 8 प्रस्तुत की हैं । कच्ची सामग्री, कल पुर्जों, उपयोगिताओं और प्रत्यक्ष लेबर के लिए आबंटन वास्तविक आधार पर किए गए हैं । विनिर्माण संबंधी ऊपरी खर्चों को उत्पादन की मात्रा के अनुपात में दर्शाया गया है । प्रशासनिक ऊपरी खर्चों तथा बिक्री एवं वितरण लागतों को बिक्री राशि के अनुसार आवंटित किया गया है । वर्ष 2001 से कंपनी और उसकी कुछ सहायक कंपनियों ने ऋणों पर ब्याज के भुगतान तथा विभिन्न मूलधन में चूक की है और उन्होंने अन्य ऋणों के संबंध में भी तकनीकी चूक की है । कंपनी को 31 दिसंबर, 2002 को समाप्त अवधि के लिए *** मिलियन अमरीकी डॉलर का निवल घाटा हुआ था । 12 मार्च, 2001 को कंपनी ने कुछ को छोड़कर अपने ऋणदाताओं के कारण सभी दायित्वों (मूलधन और ब्याज) के भुगतान पर रोक की घोषणा की थी । रोक की घोषणा के बाद कंपनी ने आम राय से ऋण के पुनर्गठन हेतु वार्ताकारी संबंध बनाए थे । कंपनी ने अब मास्टर पुनर्गठन करारों पर हस्ताक्षर किए हैं । इस एम आर ए

और अन्य पुनर्गठन संबंधी दस्तावेजों से निश्चयात्मक पुनर्गठन करार की उत्पत्ति होती है । इस एम आर ए की सफलता अनेक कारणों पर निर्भर है जिन्हें वित्तीय विवरणों में रेखांकित किया गया है । तथापि, इस जांच हेतु वित्तीय व्यय (विनिमय घाटे सहित) के आवंटन के प्रयोजनार्थ कंपनी ने यह अनुमान लगाया है कि एम आर ए का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा चुका है और उन्होंने तदनुसार अपनी देनदारियों और खर्चों को बताया है । परिशिष्ट 7 में कंपनी ने *** मिलियन अमरीकी डॉलर (कलेंडर वर्ष 2000 के लिए) के वित्तीय विवरणों के बजाय *** मिलियन अमरीकी डॉलर के वित्तीय व्यय का दावा किया है । कंपनी का दावा है कि एम आर ए के अंतर्गत निर्धारित शर्तें कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य हैं और इस प्रकार उन्होंने उक्त करार के अनुसार अपनी देय राशियों की पुनः गणना की है । सत्यापन दल ने यह उल्लेख किया है कि मास्टर पुनर्गठन करार की सफलता अनेक कारकों (जो पर्याप्तः अनिर्धारणीय हैं और कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं) पर निर्भर है । इसके अलावा सत्यापन के समय तक पुनर्गठन लागू होने के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । भुगतान योग्य देनदारियों की राशि में किसी समायोजन को उनके लेखा परीक्षित लेखों में दर्शाया जाना चाहिए । इस विशेष मामले में एक वर्ष बाद भी कोई समायोजन नहीं किया गया है । सत्यापन रिपोर्ट और प्रकटन विवरण जारी करने के बाद निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि उसका वित्तीय व्यय तथा लाभ को प्राधिकारी द्वारा उसकी वास्तविक देनदारियों के आलोक में संशोधित किए जाने की जरूरत है और उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में संशोधित करार प्रस्तुत किया है । तथापि, प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती निर्धारण के अनुसार वित्तीय व्यय एवं उचित लाभ के निर्धारण की अपनी पद्धति को दोहराते हैं ।

(ख) अनुच्छेद 2.2 के अनुसार उत्पादन लागत के निर्धारण हेतु अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुसार लागतों की गणना सामान्यतः जांचाधीन उत्पादन अथवा निर्यातक द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर की जाएगी बशर्ते कि ऐसे रिकार्ड निर्यातक देश के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के अनुसार हों । कंपनी के प्रकाशित वित्तीय विवरणों को निर्यातक देश के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सत्यापित किया गया है । जी ए ए पी के अनुसार उपलब्ध वित्तीय विवरण को देखते हुए कंपनी द्वारा ब्याज संबंधी व्यय के आवंटन हेतु एम आर ए के परवर्ती विकास पर कंपनी द्वारा व्यक्त किए गए भरोसे को उचित नहीं माना गया था । तदनुसार बनाने और बेचने की कुल लागत को संशोधित किया गया है । इनके ब्यौरे गोपनीय सत्यापन रिपोर्टों में अनुबंध क, ख और ग के रूप में संलग्न किए गए हैं । चूंकि घरेलू बिक्री कीमत जांच अवधि के दौरान भारित औसत आधार पर उत्पादन लागत से कम है इसलिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण इस जांच में नहीं किया जा सकता और इस प्रकार सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का उपयोग करते हुए किया गया है । परिकलित सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत में *** का लाभ मार्जिन उपलब्ध कराने के बाद किया गया है ।

(ii) मै. पिंडो डेली पल्प एंड पेपर मिल्स, इंडोनेशिया

(क) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण इंडोनेशिया में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (इंडोनेशिया जी ए ए पी) के अनुसार

तैयार किए गए हैं । यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिसका उपयोग इंडोनेशिया की अधिकांश कंपनियों द्वारा किया जाता है । कंपनी द्वारा अपनी रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ मासिक लाभ एवं हानि लेखे तथा उत्पादन लागत संबंधी रिपोर्टें तैयार की जाती हैं । कंपनी ने अपनी प्रचालन एवं वित्तीय सूचना प्रणाली के लिए एस ए पी प्रणाली लागू की है । मै. पिंडो डेली ने जांच दल को उत्पादन लागत के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं । कंपनी का रिपोर्टिंग वर्ष कलेंडर वर्ष है जो जांच अवधि के अनुरूप है । परिशिष्ट 7 और 8 में प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन किसी प्रैक्टिसकर्ता लेखाकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है जिसे कंपनी ने उपलब्ध नहीं कराया है । जांच अवधि के दौरान कोटेड पेपर और पेपर बोर्ड का कुल उत्पादन *** मी.टन (क्षमता उपयोग***) हुआ था । जांच अवधि के दौरान कुल बिक्री *** मी.टन की हुई थी । कंपनी ने परिशिष्ट 7 और 8 प्रस्तुत की हैं । कच्ची सामग्री, कलपुर्जों, उपयोगिताओं और प्रत्यक्ष श्रम के लिए आवंटन वास्तविक आधार पर किए गए हैं । प्रशासनिक ऊपरी खर्चों तथा बिक्री एवं वितरण लागतों को बिक्री राशि के अनुसार आवंटित किया गया है । वर्ष 2001 से कंपनी और उसकी कुछ सहायक कंपनियों ने ऋणों पर ब्याज के भुगतान तथा विभिन्न मूलधन में चूक की है और उन्होंने अन्य ऋणों के संबंध में भी तकनीकी चूक की है । कंपनी को 31 दिसंबर, 2002 को समाप्त अवधि के लिए *** मिलियन अमरीकी डॉलर का निवल घाटा हुआ था । 12 मार्च, 2001 को *** और उसकी सहायक कंपनियों, जिनमें कंपनी तथा ***भी शामिल है ने कुछ को छोड़कर अपने ऋणदाताओं के कारण सभी दायित्वों (मूलधन और ब्याज) के भुगतान पर रोक की घोषणा की थी । रोक की घोषणा के बाद एपीपी ने आम राय से ऋण के पुनर्गठन हेतु वार्ताकारी संबंध बनाए थे । कंपनी ने अब

मास्टर पुनर्गठन करारों पर हस्ताक्षर किए हैं । इस एम आर ए और अन्य पुनर्गठन संबंधी दस्तावेजों से निश्चयात्मक पुनर्गठन करार की उत्पत्ति होती है । इस एम आर ए की सफलता अनेक कारणों पर निर्भर है जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में रेखांकित किया गया है । तथापि, इस जांच हेतु वित्तीय व्यय (विनिमय घाटे सहित) के आवंटन के प्रयोजनार्थ कंपनी ने यह अनुमान लगाया है कि एम आर ए का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा चुका है और उन्होंने तदनुसार अपनी देनदारियों और खर्चों को बताया है । परिशिष्ट 7 में कंपनी ने *** मिलियन अमरीकी डॉलर (कलेंडर वर्ष 2000 के लिए) के वित्तीय विवरणों के बजाय *** मिलियन अमरीकी डॉलर के वित्तीय व्यय का दावा किया है । कंपनी का दावा है कि एम आर ए के अंतर्गत निर्धारित शर्तें कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य हैं और इस प्रकार उन्होंने उक्त करार के अनुसार अपनी देय राशियों की पुनः गणना की है । सत्यापन दल ने यह उल्लेख किया है कि मास्टर पुनर्गठन करार की सफलता अनेक कारकों (जो पर्याप्तः अनिर्धारणीय हैं और कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं) पर निर्भर है । इसके अलावा सत्यापन के समय तक पुनर्गठन लागू होने के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । भुगतान योग्य देनदारियों की राशि में किसी समायोजन को उनके लेखा परीक्षित लेखों में दर्शाया जाना चाहिए । इस विशेष मामले में एक वर्ष बाद भी कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

- (ख) सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद सत्यापन दल ने यह नोट किया है कि मास्टर पुनर्गठन करार की सफलता अनेक कारकों (जो पर्याप्तः अनिर्धारणीय हैं और कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं) पर निर्भर है । इसके अलावा सत्यापन के समय तक पुनर्गठन लागू होने के बारे में कोई साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं किया गया है । भुगतान योग्य देनदारियों की राशि में किसी समायोजन को उनके लेखा परीक्षित लेखों में दर्शाया जाना चाहिए । इस विशेष मामले में एक वर्ष बाद भी कोई समायोजन नहीं किया गया है । सत्यापन रिपोर्ट और प्रकटन विवरण जारी करने के बाद निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि उसका वित्तीय व्यय तथा लाभ को प्राधिकारी द्वारा उसकी वास्तविक देनदारियों के आलोक में संशोधित किए जाने की जरूरत है और उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में संशोधित करार प्रस्तुत किया है । तथापि, प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती निर्धारण के अनुसार वित्तीय व्यय एवं उचित लाभ के निर्धारण की अपनी पद्धति को दोहराते हैं ।

- (ग) अनुच्छेद 2.2 के अनुसार उत्पादन लागत के निर्धारण हेतु अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुसार लागतों की गणना सामान्यतः जांचाधीन उत्पादन अथवा निर्यातक द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर की जाएगी बशर्ते कि ऐसे रिकार्ड निर्यातक देश के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के अनुसार हों । कंपनी के प्रकाशित वित्तीय विवरणों को निर्यातक देश के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सत्यापित किया गया है । जी ए ए पी के अनुसार उपलब्ध वित्तीय विवरण को देखते हुए कंपनी द्वारा ब्याज संबंधी व्यय के आवंटन हेतु एम आर ए के परवर्ती विकास पर कंपनी द्वारा व्यक्त किए गए भरोसे को उचित नहीं माना गया था । तदनुसार बनाने और बेचने की कुल लागत को संशोधित किया गया है । इनके ब्यौरे अनुबंध क, ख और ग के रूप में संलग्न किए गए हैं । परिकलित सामान्य मूल्य का निर्धारण 5% के लाभ मार्जिन का प्रावधान करने के बाद किया गया है । चूंकि घरेलू बिक्री कीमत जांच अवधि के दौरान भारित औसत आधार पर उत्पादन लागत से

कम है इसलिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण इस जांच में नहीं किया जा सकता और इस प्रकार सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का उपयोग करते हुए किया गया है । परिकलित सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत में 5% का लाभ मार्जिन उपलब्ध कराने के बाद किया गया है । प्रकटन विवरण के बाद घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि प्राधिकारी को डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार निर्यात कीमत स्वीकार करनी चाहिए थी । इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच आई बी आई एस के आंकड़ों (आई बी आई एस द्वारा उपलब्ध सीमाशुल्क दैनिक सूची से लिए गए और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों) के अनुसार शुरू की गई थी । जांच की शुरुआत के बाद जिन निर्यातकों ने जांच अवधि के दौरान भारत को समग्र निर्यात किए थे, उन्होंने भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों की मात्रा और कीमत के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए थे । इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के समय आई बी आई एस के आंकड़ों में सूचित निर्यात कीमत को स्वीकार किया है तथा सभी समायोजन सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार किए गए हैं जो कि भारत को निर्यात संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए निर्यातकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य प्रक्रिया है ।

तुलना

24. कारखाना द्वार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना करने के प्रयोजनार्थ अंतरों के लिए समायोजनों के रूप में उचित छूट की अनुमति दी गई है जिनका दावा किया गया है और जिन्हें कीमत एवं कीमत तुलनीयता

प्रवाहित करने के लिए प्रदर्शित किया गया है । ये समायोजन परिवहन, बीमा, हैंडलिंग, लदान, ऋण लागत और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 6 के अनुसार अन्य के संबंध में जहां उचित पाया गया है, किए गए हैं ।

टी के और पी डी, इंडोनेशिया के लिए पाटन मार्जिन

25. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के नियम 6 (iv) के अनुसार पाटन मार्जिन का निर्धारण भारित औसत निर्यात कीमत के साथ परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर किया गया था । उक्त तुलना में जांच अवधि के दौरान निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटन का पता चला था । निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और यह दोनों ही निर्यातकों के लिए सकारात्मक है ।

इंडोनेशिया से अन्य निर्यात:

26. चूंकि इंडोनेशिया से कुल आयातों की समग्र मात्रा की तुलना में टी.के. और पी.डी. से हुए आयातों की मात्रा (वस्तुतः इंडोनेशिया से जांच अवधि के दौरान केवल इन दो निर्यातकों से सभी निर्यात हुए थे) बहुत अधिक थी इसलिए अवशिष्ट निर्यातकों के लिए अवशिष्ट आयात मार्जिन निर्धारित किया गया है जैसा कि मै. पिंडो डेली, इंडोनेशिया के लिए निर्धारित किया गया है ।

पाटन मार्जिन:**27. पाटन मार्जिन:**

देश	उत्पादक/निर्यातक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन %
ई.यू.	मै. सैपी यूरोप	****	****	24%
	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	****	****	35%
इंडोनेशिया	पिंडो डेली	****	****	44.2
	टी.के.	****	****	33.5
	अन्य	****	****	44.2

(छ) क्षति**(क) घरेलू खपत/मांग:**

28. घरेलू खपत/मांग घरेलू उद्योग की बिक्रियां संबद्ध देशों से आयातों और भारत में अन्य देशों से आयातों पर आधारित हैं । इस आधार पर घरेलू मांग अथवा घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की खपत जनवरी-दिसंबर, 2000 में 83194 मी.ट. से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 110721 मी.ट. हो गई जिसमें 33% की वृद्धि हुई । ये देखा जा सकता है कि देश में कुल मांग प्रति वर्ष के आधार पर भी बढ़ रही है ।

घरेलू मांग/खपत			
	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं., 01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
मांग (मी.ट.)	83194	90597	110721
सूचीबद्ध	100.00	108.90	133.09

29. (क) संबंधित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन

- (1) प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या ई.यू. और इंडोनेशिया से उद्गमित संबद्ध वस्तुओं के आयातों की सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अधीन पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार संचयी रूप से जांच की जानी चाहिए ।
- (2) संबद्ध देशों (ई.यू. और इंडोनेशिया) में प्रत्येक से आयातों के संबंध में साबित पाटन मार्जिन पाटन रोधी करार के अनुच्छेद 5.8 और पाटन रोधी नियमावली के नियम 14 में यथा परिभाषित न्यूनतम से अधिक था और इनमें से प्रत्येक देश से पाटित आयातों की मात्रा नगण्य नहीं थी ।
- (3) घरेलू उत्पाद और विभिन्न देशों में उत्पादकों द्वारा आपूर्ति उत्पाद समान वस्तु हैं और आयाजित उत्पादों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को एक-दूसरे स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है और किया जा रहा है । विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों और उसकी घरेलू उद्योग द्वारा ग्राहकवार बिक्रियों से यह साबित होता है कि अनेक ऐसे पक्षकार थे जिन्होंने घरेलू उद्योग से खरीद की और संबद्ध देशों से आयात किए । यह भी नोट किया गया कि विभिन्न देशों द्वारा आपूर्ति संबद्ध वस्तु की उसी बाजार में प्रतिस्पर्धा हुई । इसके अलावा यह भी नोट किया गया कि संबद्ध देशों के विभिन्न उत्पादकों द्वारा आपूर्ति उत्पादों का तुलनीय बिक्री माध्यमों और समान वाणिज्यिक परिस्थितियों में भारत में विपणन किया गया ।

- (4) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने यह विचार किया कि पाटन रोधी करान के अनुच्छेद 3.3 में निर्धारित मानदंड और नियम-11 के अंतर्गत अनुबंध 11 के पैरा iii के अनुसार मानदंड ई.यू. और इंडोनेशिया से आयातों के संबंध में पूरे किए गए थे और इसलिए इन दोनों देशों के आयातों को क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ एकत्र किया जाना चाहिए ।

(ख) संबद्ध देशों से उदगमित आयात:

मात्रा:

30. घरेलू बाजार में संबद्ध देशों से विचाराधीन उतद के पाटित आयातों की कुल मात्रा में विचाराधीन अवधि के दौरान 140% की वृद्धि हुई । कुल मांग के हिस्से के रूप में यह 81% बढ़ा है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन अवाधे के दौरान घरेलू खपत 33% तक बढ़ी । इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि मांग में क्रमिक और पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा पाठित आयातों की मात्रा में विचाराधीन अवधि के दौरान काफी बढ़ोत्तरी हुई है ।

सकल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा			
देश (मी.ट.)	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
यूरोपीय संघ (मी.ट.)	10027	15962	24323
इंडोनेशिया (मी.ट.)	4057	2750	9592
संबद्ध देशों से कुल आयात	14084	18712	33914
अन्य देश	5413	3059	3043
अन्य देशों का हिस्सा	27.76%	14.05%	8.23%
कुल आयात	19496	21771	36957

(ग) सकल आयातों में संबद्ध देशों का हिस्सा:

31. विचाराधीन अवधि के दौरान सकल आयातों से संबद्ध देशों से पाठित आयातों का हिस्सा 27% अंकों से बढ़ा । सकल आयातों में पाठित आयातों के बाजार हिस्से में 2000 में 72% से वृद्धि होकर जांच अवधि के दौरान 91% हो गया । इसलिए यह नोट किया जाता है कि पाठित आयातों का हिस्सा सकल आयातों के हिस्से में काफी बढ़ा है ।

सकल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा			
	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
यूरोपीय संघ (मी.ट.)	10027	15962	24323
बाजार का हिस्सा	51.43%	73.32%	65.81%
इंडोनेशिया (मी.ट.)	4057	2750	9592
बाजार का हिस्सा	20.81%	12.63%	25.95%
संबद्ध देशों से कुल आयात	14084	18712	33914
संबद्ध देशों से पाठित आयातों का बाजार हिस्सा	72.24%	85.95%	91.77%
अन्य देश (मी.ट.)	5413	3059	3043
अन्य देशों का हिस्सा	27.76%	14.05%	8.23%
कुल आयात	19496	21771	36957

32. उपर्युक्त जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कुल मांग के हिस्से के रूप में संबद्ध देशों के पाटित आयातों के बाजार हिस्से में काफी वृद्धि हुई है और यह गत वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान काफी बढ़ गया है ।

(घ) कीमतें:

विचाराधीन अवधि के दौरान कीमत का परिकलन

33. वर्ष 2001-02 और जांच अवधि के बीच संबद्ध देशों में उद्गमित आयातों की औसत सीआईएफ कीमतों में विचाराधीन अवधि अथवा क्षति अवधि के दौरान 10.75% तक कमी आई ।

	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
पाटित आयातों की सी.आई.एफ. कीमत (रु./मी.ट.)	38967	33782	34779
सूचीबद्ध	100.00	86.69	89.25
घरेलू कीमतें (रु./मी.ट.)	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	97.63	96.01

(ङ) कीमतों में कटौती (पीयूसी)

34. निर्यातक उत्पादकों और घरेलू बाजार में औसत बिक्री कीमत के बीच संबंधित उत्पाद की तुलनीय किस्मों के लिए एक तुलना की गई थी जिसमें सभी छूटों और

करों जो ग्राहकों से संबंधित नहीं थे उसी स्वर पर व्यापार में शामिल नहीं थे । घरेलू उद्योग की कीमतें कारखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित की गई थी । संबंधित संबद्ध देशों की सीआईएफ आयात कीमतें मूल सीमा शुल्क के विगत आयातों के लिए समायोजित की गई थी । इस तुलना से यह मालूम हुआ कि संबद्ध देशों में उद्गमित संबद्ध वस्तुओं को घरेलू बाजार में ऐसी कीमतों पर बेचा गया था जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हुई थी । जब इसको घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमतों के रूप में व्यक्त बताया गया था । वस्तुतः कीमत कटौती का मार्जन ई.यू. से उद्गमित अथवा निर्यातित आयातों के संबद्ध कीमत कटौती का मार्जन पर्याप्त रूप से नकारात्मक था जबकि यह इंडोनेशिया से निर्यातित अथवा उद्गमित संबद्ध वस्तुओं के बारे में सकारात्मक था । तथापि, यह जब दोनों देशों को एकत्र किया गया था पर्याप्त रूप से नकारात्मक था । प्रकटन विवरण जारी करने के बाद यह तर्क जारी किया गया है कि मूल्य में कटौती प्रत्येक अलग-अलग संबद्ध देश के लिए नहीं बल्कि संचयी रूप में परिकलित की जानी चाहिए । प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि मिलने में कटौती को अलग-अलग और संचयी रूप से प्रदर्शित किया गया है ।

पी.यू.सी. और क्षति मार्जिन (रु./मी.ट.)			
	ई.यू.	सूची संबद्ध देश	इंडोनेशिया
सी.आई.एफ. मूल्य	35947.98	34778.94	31758.92
पहुंच मूल्य	47199.70	45664.75	41699.46
बिक्री मूल्य	****	****	****
कीमत कटौती	****	****	****
कीमत कटौती प्रतिशत श्रृंखला	(10-15)	(8-12)	(0-1)

(च) कम कीमत पर बिक्री (पी.यू.सी):

35. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस दावे की भी जांच की है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से लाभकारिता में गिरावट के कारण घाटा हो रहा है । प्राधिकारी ने नोट किया कि कम कीमत पर बिक्री क्षति के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक है । प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत का परिकलन किया है और इसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा की गणना करने के लिए पहुंच मूल्य के साथ की है । विश्लेषण से कम मूल्य पर बिक्री के मामले का अमहत्वपूर्ण स्तर मालूम हुआ जिससे संचित रूप से परिकलन करने पर घरेलू उद्योग को क्षति हुई । प्रकटन विवरण के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों के उत्तर में यह बताया गया है कि कम कीमत पर बिक्री (क्षति मार्जिन) को एक साथ सभी संबद्ध देशों के साथ-साथ अलग-अलग संबद्ध देशों के लिए संचयी रूप से भी निर्धारित किया गया है ।

पी.यू.सी. और क्षति मार्जिन (रु./मी.ट.)			
	ई.यू.	सभी संबद्ध देश	इंडोनेशिया
सी.आई.एफ. मूल्य	35947.98	34778.94	31758.92
पहुंच मूल्य	****	****	****
बिक्री मूल्य	****	****	****
गैर-क्षतिकारक कीमत	****	****	****
क्षति मार्जिन	(-)	****	****
क्षति मार्जिन श्रृंखला	(0.5-2.0)	3-5%	10-13%

(छ) कीमत में कमी:

36. जैसा कि पूर्व पैराग्राफ में नोट किया गया है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें 2000-01 की तुलना में जांच अवधि के दौरान मामूली कम हुई हैं। प्राधिकारी का जांच के आधार पर यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातों के कारण कीमत में अमहत्वपूर्ण कमी करनी पड़ रही है।

घरेलू कीमत (रु./मी.ट.)	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	97.63	96.01

(ज) घरेलू उद्योग की स्थिति:**प्रारम्भिक टिप्पणियां:**

37. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैराग्राफ (iv) के अनुसार संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की जांच में घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले घटक, बिक्रियों में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार का हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर लाभ अथवा क्षमता उपयोग, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, वस्तु सूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की सक्षमता सहित उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संबंधित आर्थिक कारक और सूचक शामिल होंगे। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क प्रस्तुत किए हैं कि जांच अवधि (पी.ओ.आई.) के दौरान घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि प्राधिकारी यह जांच करने के लिए बाध्य हैं कि क्या पाटन

का निरंतर खतरा है और क्षति के साथ कोई कारणात्मक संबंध है और प्राधिकारी को इस संबंध में स्वतंत्र रूप से पाटन मार्जिन निर्धारण की किसी एक अथवा सभी संगत सूचना की जांच अवश्य करनी चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार पाटित कीमतों अथवा गैर क्षतिकारक से कम कीमत पर आयातों का कोई खतरा नहीं है और इसके परिणामस्वरूप लगातार क्षति होने का कोई खतरा नहीं है। बहुत से हितबद्ध पक्षकारों ने भारत में घरेलू उद्योग के वेबसाइट में शामिल रिपोर्टों का उल्लेख किया है और कहा है कि इन सूचनाओं से भारत में वर्तमान और संभावित बाजार स्थितियों की एक बुलाबी तस्वीर प्रदर्शित होती है। निर्यातकों और आयातकों के हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पाटन रोधी करार के 3.4 में यथा उल्लिखित अधिकांश क्षति मानदंडों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति प्रदर्शित नहीं होती। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उन्हें बाजार के घटते हुए हिस्से, लाभकारिता, आर.ओ.आई. और पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के कारण क्षति हुई है। प्रकटन विवरण जारी होने के बाद घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि ए डी ए के 3.4 के अनुसार क्षति संबंधी विभिन्न मानदंडों से घरेलू उद्योग को क्षति के अलग-अलग स्तर का पता चलता है और उन्होंने इस मामले में कुछ न्याय सिद्धांत संलग्न किए हैं। दूसरी ओर विभिन्न निर्यातकों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि संबद्ध देशों से आयातों की संवर्धित मात्रा के कारण कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और घरेलू उद्योगों को क्षति का पता नहीं चलता है क्योंकि अनेक मापदंड से नकारात्मक निर्धारण प्रदर्शित होते हैं। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के निर्धारण से संबंधित तर्कों के बारे में यह उल्लेख किया जाता है कि क्षति रहित कीमत वास्तविक उत्पादन लागत तथा घरेलू उद्योग के अन्य तकनीकी मापदंडों पर आधारित है और क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए उचित लाभ जोड़ा गया है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी

निवेदनों का ए.डी.ए. के 3.4 में यथा उल्लिखित विभिन्न सूचकों के अनुसार विश्लेषण किया गया है जो इस प्रकार है :-

(क) उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग:

38. निम्न तालिका से यह देखा जा सकता है कि जनवरी-दिसंबर, 2000 की तुलना में जनवरी, 2001-दिसंबर, 2001 के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2.6% की गिरावट आई जबकि जांच अवधि के दौरान मामूली सुधार हुआ परंतु वह आधार वर्ष के साथ तुलना करने पर अब भी कम है। विचाराधीन अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाए कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जनवरी-दिसंबर, 2000 की तुलना में जांच अवधि के दौरान मामूली सा 2.15% कम हो गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च मात्रा से भी अधिक क्षमता उपयोग में कमी होने से बढ़ती हुई मांग के परिदृश्य में घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग क्षति निर्धारण की अवधि के दौरान काफी अधिक होता रहा है। इसके अतिरिक्त, मांग में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो जाने पर भी घरेलू उद्योग द्वारा उस अवधि के दौरान क्षमता का कोई सृजन नहीं किया गया। उपर्युक्त के आधार पर यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग पर इस मानदंड के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग (परतयुक्त सहित बिना परत वाले कागज और कागज बोर्ड)			
	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
क्षमता (मी.ट.)	115000	115000	115000
उत्पादन (मी.ट.)	104810	101817	102336
क्षमता उपयोग %	91.94	88.54	88.99

(ख) बिक्रियों की मात्रा:

39 निम्न तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, यह देखा जाना है कि घरेलू उद्योग मामूली कीमतें कम करके अपनी बिक्री मात्रा कायम रख सका क्योंकि घरेलू उद्योग अपने ग्राहकों को नहीं खो सकता था। यह भी देखा जा सकता है कि क्षति की अवधि में सकल मांग/खपत में 33% (27527 मी.ट.) की वृद्धि हुई है जबकि याचिकाकर्ता की बिक्रियों की मात्रा उसी अवधि में सामान्य रूप से 9% (5997 मी.ट. मात्र) बढ़ी है। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बिक्रियों की मात्रा में वृद्धि को इस तथ्य के कारण से पर्याप्त नहीं समझा जा सकता कि उसी अवधि में मांग में 33% बढ़ोत्तरी हुई है। प्राधिकारी द्वारा यह पुनः कहा जाता है कि बिक्री की मात्रा इस तथ्य के कारण बढ़ी हुई नहीं हो सकती कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षति निर्धारण अवधि के दौरान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की गई थी और इस प्रकार उनके उत्पादन से संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बगैर भी घरेलू मांग पूरी नहीं हो सकती थी। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्रियों के अतिरिक्त पर्याप्त निर्यात किए। इस प्रकार उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस मानदंड के कारण हुई किसी क्षति के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं।

वर्ष	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं., 01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
बिक्री	****	****	****
रुख	100.00	108.05	109.41

(ग) बिक्री कीमतें:

40. निम्न तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें सुसंगत रूप से कम हो रही हैं । तथापि, बिक्री कीमतों में कमी मामूली रही है और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में होने वाली कमी के साथ-साथ हुई है । इस तथ्य की दृष्टि से कि क्षति निर्धारण अवधि के दौरान बिक्री कीमत में बहुत ही कम गिरावट आई है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को इस मानदंड के अकारण बहुत अधिक क्षति हुई है ।

	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
रू./मी.ट.	****	****	****
सूचीबद्ध	100	98	96
सीओपी/मी.ट.	****	****	****
सूचीबद्ध	100	95.19	95.84

घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें:**(घ) बाजार में हिस्सा:**

निम्न तालिका से यह मालूम होता है कि याचिका कर्ता का बाजार का हिस्सा जांच अवधि में 76% से कम होकर क्षति की अवधि के दौरान 62% हो गया है । उसी अवधि में पाटित आयातों का बाजार में हिस्सा 16% से बढ़कर 30% हो गया है । यह भी नोट किया जाए कि क्षति की अवधि के दौरान भारत के बाजार में 33% की बढ़ोत्तरी हुई । प्रकटन विवरण के बाद यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में कमी को क्षति के सही साक्ष्य के रूप में लिया जाना

चाहिए जैसा कि सामान्य तौर पर अन्य देशों में किया जाता है । घरेलू उद्योग ने अन्य देशों की प्रथाओं के साथ-साथ इस मामले में विभिन्न न्याय निर्णय उद्धृत किए हैं । घरेलू उद्योग के तर्कों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने यह नोट किया कि बाजार के हिस्से में गिरावट को क्षति के सही निर्धारण के लिए लिया जा सकता है जबकि घरेलू उद्योग मांग में हुई वृद्धि की दृष्टि से अपने बाजार के हिस्से में बढ़ोत्तरी कर सकता था । तथापि, संबद्ध मामले में घरेलू उद्योग के पास बढ़ती हुई मांग की दृष्टि से अधिक क्षमता उपयोग से भी अपना उत्पादन और बिक्री की मात्रा बढ़ाने की क्षमता नहीं है, अतः बाजार के हिस्से में गिरावट घरेलू उद्योग की अपर्याप्त क्षमता का स्वाभावित स्वरूप है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह नोट किया गया है कि बाजार के हिस्से में गिरावट को संबद्ध जांच में घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारक नहीं माना जा सकता ।

मांग में घरेलू उद्योग का बाजार में हिस्सा			
	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
याचिकाकर्ता द्वारा धारित % हिस्सा			
	76.57	75.97	62.95
अन्य उत्पाद	0.00	0.00	3.67
घरेलू उत्पाद	76.57	75.97	66.62
संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु	16.93	20.65	30.63
अन्य आयात	6.51	3.38	2.75

(ड) स्टॉक:

41. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का स्टॉक वर्ष 2000 में 5227 मी.ट. से घटकर 2001 में 4767 मी.ट. रह गया है और जांच अवधि में 4445 मी.ट. हो गया है । वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में 8.8% की कमी हुई है

और जांच अवधि के दौरान यह 6.16% तक कम हो गया । यह समझा जाता है कि घरेलू उद्योग को इस मानदंड के कारण क्षति नहीं हुई है ।

माल सूचियों पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव			
	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
माल सूची/स्टॉक	****	****	****
घरेलू बिक्री की मात्रा की सूची	100	108	109
उत्पादन	****	****	****
माल सूचियां/उत्पादन	5.0	4.7	4.3
बिक्री की मात्रा के % के रूप में माल सूची	8.21	6.93	6.38
सूचीबद्ध स्टॉक	100.00	91.20	85.04

(च) लाभकारिता:

42. पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों में कमी से पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभकारिता प्रभावित हुई मालूम होती है । तथापि, आधार वर्ष की तुलना में लाभकारिता पर कोई अधिक प्रतिकूल रुख मालूम नहीं हुआ हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में लाभकारिता में गिरावट आई है । प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इन निवेदनों से सहमत हैं कि जांच अवधि के दौरान कुल मिलाकर हाल के विगत से साक्ष्य से घरेलू उद्योग की संभावित भावी स्थिति के सबसे मजबूत संकेत उपलब्ध होते हैं ।

प्रवृत्तियों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग को पिछले वर्ष की तुलना में लाभकारिता हानि हुई है ।

लाभकारिता			
वर्ष	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
प्रति इकाई लाभ/घाटा (रू./मी.ट.)	****	****	****
सूची	100.00	148.7	99.6
ब्याज के बाद निवल लाभ/घाटा (लाख रू.)	****	****	****
सूची	100.00	160.6	108.96

(छ) नकदी प्रवाह:

43. चूंकि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु के अलावा बिना परत वाले कागज का निर्माण कर रहा है इसलिए प्राधिकारी क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के लिए अलग से नकदी प्रवाह की गणना नहीं कर सकते । तथापि, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि में नकद लाभ के कारण किसी प्रतिकूल रुख से घाटा हुआ मालूम नहीं होता ।

नकद लाभ			
	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
नकद लाभ वास्तविक लाख	****	****	****
सूची	100.00	120.98	111.56
नकद लाभ/मी.टन	****	****	****
सूची	100	111.98	101.94

(ज) निवेश पर लाभ:

44. निम्नलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि निवेश पर लाभ आधार वर्ष जन.-दिसं. 2000 की तुलना में जांच अवधि के दौरान लगभग 25% तक कम हो गया है ।

नियोजित पूंजी और निवेश पर लाभ			
वर्ष	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
नियोजित पूंजी	****	****	****
सूची	100.0	96.03	101.17
पी.बी.आई.टी.	****	****	****
सूची	100.00	90.09	76.79
नियोजितपूंजी पर लाभ	****	****	****
सूची	100.00	93.81	75.91

(झ) पूंजी जुटाने की योग्यता:

45. प्राधिकारी ने इस मानदंड की जांच की है और यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि इस पर क्षति निर्धारण की अवधि के दौरान इस मानदंड द्वारा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(-I) रोजगार और वेतन:

46. वर्ष 2000 में 869 की जनशक्ति जांच अवधि के दौरान घटकर 784 रह गई है ! तथापि, इस मानदंड के कारण कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है क्योंकि कंपनी में अन्य उत्पादों का निर्माण किया गया है, इसलिए प्राधिकारी इस मानदंड के कारण क्षति का निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव नहीं करते हैं ।

रोजगार और वेतन पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव			
	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
कर्मचारियों की संख्या	****	****	****
% परिवर्तन		-6.33	-3.69
बिक्रियां/कर्मचारी	73.30	84.55	88.90

निम्नलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि श्रमिकों को दिए गए वेतन में कोई गिरावट नहीं आई है ।

वर्ष	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
कुल वेतन (लाख रु.)	****	****	****
वेतन/कर्मचारी (रु.)	****	****	****
सूची	100.00	115.16	125.35
उत्पादन की प्रति यूनिट पर वेतन (रु./किग्रा.)	****	****	****
सूची	100.00	107.87	113.09

(ट) उत्पादकता:

47. वर्ष 2000, 2001 और 2002 की अवधियों के लिए प्रति कर्मचारी की उत्पादकता निम्न प्रकार है :-

उत्पादकता			
	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
कारोबार लाख	****	****	****
कर्मचारी	869	814	784
उत्पादकता %	****	****	****
सूची	100.00	106.76	110.84

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है । अतः उत्पादकता में कमी होना ऐसा कोई कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो ।

(ठ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक:

48. निम्न तालिका से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है कि संबद्ध देशों की कीमतें वर्ष 2000 में 38967 रु. से कम होकर जांच अवधि के दौरान 34779 रु. रह गई हैं ।

	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
पाटित आयातों की सी.आई.एफ कीमत (रू./मी.ट.)	38967	33782	34779
सूचीबद्ध	100.00	86.69	89.25
घरेलू कीमतें (रू./मी.ट.)	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	97.63	96.01

उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुएं निरंतर कम कीमतों पर आ रही हैं । यह माना जा सकता है कि अन्य कारकों के साथ-साथ आयातों के स्तर से घरेलू कीमतें निर्धारित होती हैं । घरेलू बाजार में बाजार कीमतें पाटित आयातों की अधिक मात्राओं से कम हो सकती हैं । तथापि, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत भी पर्याप्त रूप से कम हो गई है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कमी की तुलना में अधिक कम हो गई है । इसके अतिरिक्त हालांकि जांच अवधि के दौरान आयात कीमतें बढ़ी हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में हैं । परंतु, घरेलू बिक्री कीमतें उत्पादन की लागत की कमी से लगभग वही रही है ।

वर्ष	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
निवल बिक्री वसूली/मी.ट	****	****	****
प्रवृत्ति	100.00	97.63	96.01
सीओपी	****	****	****
सूची	100	95.19	95.84

(ढ) हाथ से निकले हुए सौदों का साक्ष्य

49. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उसने पाटित आयातों के कारण बिक्री आदेश खोए हैं और उन्होंने प्रयोक्ताओं के साथ-साथ इस संबंध में आयातकों द्वारा भेजे गए कुछ पत्र भी संलग्न किए हैं । साक्ष्य की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव है कि कुछ बिक्री आर्डर घरेलू उद्योग द्वारा खोए गए हैं, हालांकि किसी बड़े ठेके का नुकसान प्राधिकारी के ध्यान में नहीं आया है ।

(ण) डंपिंग मार्जन की मात्रा

50. डंपिंग का मार्जन इंडोनेशिया के लिए 35-44% और यूरोपीय यूनियन के लिए 24-35% है और इसे प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समझा जाता है ।

(त) वृद्धि

51. यह नोट किया जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान समग्र बाजार में 17.13% की वृद्धि मालूम हुई है । घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा भी जांच अवधि के दौरान बढ़ी है जबकि कुल बिक्री राजस्व कम हो गया है । बाजार के हिस्से (-11.8%) के अनुसार जांच अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक है । उसी समय संबद्ध देशों से आयातों में लगभग 8616 मी.ट. तक वृद्धि हुई है और कम मूल्य पर पाटित आयातों के बाजार हिस्से में लाभ 17.03% तक बढ़ गया था जो कि जांच अवधि के दौरान मालूम हुआ था । तथापि, क्षति की अवधि के दौरान फर्म की लाभकारिता में कोई महत्वपूर्ण रुख नहीं रहा है । यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान लाभकारिता में गिरावट आई है ।

वृद्धि पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव			
	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
मांग में वृद्धि (%)		2.60	17.13
याचिकाकर्ता की बिक्री मात्रा में वृद्धि (%)		8.05	1.26
याचिकाकर्ता के कारोबार में वृद्धि (%)		5.49	-0.42
लाभ/मी.ट. में वृद्धि (%)		48.70	-33.02

52. क्षति के निष्कर्ष:

जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, यद्यपि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र और तुलनात्मक दृष्टि से पर्याप्त वृद्धि हुई है, तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में मात्रात्मक प्रभाव दर्शाते हुए मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की मात्रा में वृद्धि के कारण कीमत संबंधी प्रभाव नहीं पाया गया है। संचयी रूप से परिकलित कीमत कटौती काफी नकारात्मक है जबकि कम कीमत पर बिक्री को अत्यधिक माना गया है जिससे पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की कीमतों के बीच कारणात्मक संबंध के अभाव का पता चलता है। यद्यपि समूची क्षति निर्धारण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 4% तक का अत्यंत कम कीमत ह्रास हुआ है तथापि, इसी अवधि के दौरान कीमत में कमी नहीं की गई है क्योंकि उत्पादन लागत इसी अवधि के दौरान बिक्री कीमत में गिरावट के अनुरूप रही है। प्राधिकारी

वस्तुतः यह मानते हैं कि जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी अधिक रही है। कीमत एवं मात्रात्मक प्रभावों के कारण घरेलू उद्योग पर पड़े प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि क्षति निर्धारण अवधि में घरेलू उद्योग में गिरावट प्रदर्शित नहीं हुई है। तथापि, यह गिरावट भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने में घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण आयी हुई समझी जाती है। परिणामतः यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग द्वारा धारित बाजार हिस्से में गिरावट पाटित आयातों के कारण आयी थी। इसके अलावा जहां आयात कीमतों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है वहीं घरेलू बिक्री कीमत में उत्पादन लागत लगभग एक समान रहने के कारण कमी आयी है। यद्यपि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान लाभकारिता में गिरावट आयी है, तथापि आधार वर्ष की तुलना में यह लगभग समान रही है। यद्यपि पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान निवेश पर आय में गिरावट आयी है, तथापि इस एकमात्र कारक को घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के निष्कर्ष हेतु पर्याप्त नहीं माना गया है। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित क्षति के अन्य मापदंडों के बारे में प्राधिकारी पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 में उल्लिखित उत्पादन क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री, रोजगार, मजदूरी, उत्पादकता, नकद लाभ, बिक्री के % के रूप में भंडार सूची तथा उत्पादन के % के रूप में भंडार सूची जैसे अधिकांश मापदंडों के अनुसार क्षति का निष्कर्ष नहीं निकाल सकें। प्राधिकारी ने नोट किया है यद्यपि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन काफी अधिक बना हुआ है। तथापि, संबद्ध देशों से पारित आयातों के कारण कोई वास्तविक प्रभाव अथवा वास्तविक क्षति नहीं हुई है। अतः उपर्युक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति नहीं हुई थी।

क्षति का खतरा और अन्य कारण**क. पाटित आयातों की अधिक दर :-**

53. यह देखा जा सकता है कि आयात जनवरी-दिसंबर, 2000 के दौरान 14084 मी.ट. के स्तर से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 33914 मी.ट. हो गए हैं । प्रत्येक वर्ष का रुख नीचे दिया गया है ।

ख. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा:

<u>सकल आयातों में संबद्ध देशों के आयातों का हिस्सा</u>			
	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
यूरोपीय यूनियन (मी.ट.)	10027	15962	24323
बाजार का हिस्सा	51.43%	73.32%	65.81%
इंडोनेशिया (मी.ट.)	4057	2750	9592
बाजार का हिस्सा	20.81%	12.63%	25.95%
सकल पाटित आयात (मी.ट.)	14084	18712	33914
सकल आयातों में संबद्ध देशों से पाटित आयातों का कुल हिस्सा	72.24%	85.95%	91.77%

54. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है जैसा कि उक्त तालिका से मालूम होता है । इस तथ्य की दृष्टि से संबद्ध वस्तुओं की मांग काफी अधिक दर पर बढ़ रही है । संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा इस तथ्य के कारण और बढ़ने की संभावना है कि घरेलू उद्योग देश में मांग के स्तर पर घरेलू समान उत्पाद का विनिर्माण करने की क्षमता में नहीं है ।

स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य पर्याप्त क्षमता:-

55. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों की जांच की है और कुछ निर्यातकों के रिकार्डों का सत्यापन भी किया है । यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने ए डी ए के 3.7 में परिगणित मानदंडों के बारे में प्राधिकारी के समक्ष अपने आवेदन में पर्याप्त सूचना प्रस्तुत नहीं की थी । जांच प्रारंभ करने के बाद प्राधिकारी को ई.यू. से एक निर्यातक के संबंध में और इंडोनेशिया से 2 निर्यातकों के संबंध में पर्याप्त सूचना प्राप्त हुई थी क्योंकि ई.यू. के अन्य निर्यातकों ने सहयोग नहीं किया । प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातक के आंकड़े प्राप्त किए जो ई.यू. निर्यातक के पास 74% से 95% तक क्षमता उपयोग को दर्शाते हैं जबकि इंडोनेशिया के निर्यातकों का क्षमता उपयोग 74% से 95% तक है । ई.यू. के एकमात्र सहयोगकर्ता निर्यातक से प्राप्त आंकड़ों की जांच करने के पश्चात यह भी नोट किया जाए कि अन्य देशों को उनके निर्यातों में क्षति की अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों से काफी अधिक वृद्धि हुई है और उनके अन्य देशों को सकल निर्यातों की तुलना में भारत को किए गए निर्यातों की वर्तमान मात्रा तथा उनकी घरेलू बिक्रियां सामान्य रही हैं और उनमें बहुत अधिक वृद्धि होने की उम्मीद नहीं है ।

(घ) कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव:

56. जहां तक कीमत पर प्रभाव का संबंध है, निम्नलिखित तालिका से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव मालूम होता है ।

वर्ष	घरेलू कीमत/मी.ट.
जन.2000-दिसं. 2000	100
जन.2001-दिसं. 2001	97.63
जन.2002-दिसं. 2002	96.01

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने पिछले दो वर्षों में बिक्री कीमतों को 1741 रु./मी.ट. तक कम किया है । तथापि, बिक्री कीमत में यह कमी घरेलू उद्योग की उत्पादन लागतों में तदनुरूपी कमी के साथ-साथ हुई है । इस प्रकार मूल्य में कमी की राशि को उसी अवधि में उत्पादन की लागत में हुई कमी को ध्यान में रखते हुए इस मामले में पर्याप्त नहीं समझा जा सकता । इस प्रकार निकट भविष्य में मूल्य में कमी होना नहीं समझा जा सकता जिससे घरेलू उद्योग की लाभकारिता पर प्रभाव पड़े ।

विचाराधीन उत्पाद की माल सूचियां

57. जहां तक मालसूचियों का संबंध है यह समझा जाता है कि इस मानदंड को पर्याप्त न समझा जाए क्योंकि निर्यातक उत्पादक विशेष रूप से ई.यू. के निर्यातकों ने बहुत अधिक मात्रा में घरेलू बिक्रियां की हैं और भारत को निर्यात उनके कुल

कारोबार के 1% से कम है । यह भी जांच की गई है कि उनकी पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में बहुत अधिक रही है ।

58. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिए गए आयातों के ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ को छोड़कर अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तु का आयात न्यूनतम से कम है और/अथवा जांच अवधि के दौरान अधिक कीमतों पर आ रहा है । इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ के आयात की पाटित कीमतों पर किए जा रहे हैं और न्यूनतम से अधिक सीमाओं में हैं । तथापि, यह भी कहा जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयात के आंकड़े प्राधिकारी को निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के पश्चात मात्रा और कीमत के अनुसार काफी अधिक बढ़ गए हैं । जांच अवधि के लिए आंकड़ों की जांच करने के पश्चात यह मालूम होता है कि यद्यपि क्षति निर्धारण अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है परंतु उनसे घरेलू उद्योगों की कीमत में कटौती नहीं हुई है । वस्तुतः ई.यू. से आ रहे आयातों से कीमत में कटौती पर्याप्त रूप से नकारात्मक है और सभी देशों के लिए संचयी रूप से भी - 8% से -12 % तक नकारात्मक है । बहुत ही मामूली-सी कम कीमतों पर घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री की गई है जब घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारक कीमत की संबद्ध देशों की पहुंच कीमत के साथ संचयी रूप से तुलना की जाती है । गैर-संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य बहुत अधिक नहीं है ।

59. संबद्ध वस्तुओं की मांग से निरंतर वृद्धि मालूम होती है । अतः मांग में गिरावट को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं माना जा सकता । यह भी देखा जा सकता है कि बाजार का आकार बढ़ रहा है इसलिए सवेदात्मक मांग घरेलू उद्योग को संभावित क्षति के लिए कोई कारक नहीं हो सकता ।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधक प्रथाओं और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, निर्यातकारी निष्पादन अथवा घरेलू उद्योग की उत्पादकता अथवा किसी अन्य ज्ञात कारक का प्रभाव

60. उत्पाद पर किसी व्यापार प्रतिबंधक प्रथा विचार के अंतर्गत नहीं आई है । जहां तक विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा का संबंध है यह मालूम होता है कि घरेलू और आयातित उत्पादों में एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा हो रही है और इन्हें एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया गया है । घरेलू उद्योग की निर्यात सूचना इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ अलग से है और उस पर नीचे अलग से कार्यवाही की गई है ।

अन्य कारकों का प्रभाव:

61. यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित नहीं किया कि संबद्ध देशों से पाटन को छोड़कर अन्य कारक हैं, जिनसे घरेलू कीमतों अथवा घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा हो । तथापि, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, जिनका उस सीमा तक विश्लेषण किया गया है जहां तक उन्हें जांच से संबंधित समझा गया है ।

1. प्रौद्योगिकी और सुधार

62. भारत में संबद्ध वस्तु का उत्पादन ब्लेड कोटिंग अथवा एयरनाइफ प्रौद्योगिकी के जरिए किया जाता है । तथापि, याचिकाकर्ता केवल ब्लेड कोटिंग प्रौद्योगिकी के

जरिए संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जो परतयुक्त कागज के उत्पादन के लिए उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी है । आयातित वस्तुओं का उत्पादन भी ब्लेड कोटिंग प्रौद्योगिकी से किया जा रहा है और इससे याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू तौर पर उत्पादित परतयुक्त कागज का प्रतिस्थापन होता है ।

2. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात कार्य-निष्पादन

63. निम्नलिखित तालिका से घरेलू उद्योग के निर्यात कार्य निष्पादन के ब्यौरे प्राप्त होते हैं । यह देखा जा सकता है कि निर्यातित मात्रा वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में कम हुई है । तथापि, यह पिछले वर्ष के दौरान 27,507 मी.ट. के स्तर तक दोबारा पर्याप्त रूप से बढ़ी है । इस प्रकार यह मालूम होता है कि क्षति की अवधि के दौरान निर्यात बिक्रियों में कोई रुख नहीं है ।

निर्यात कार्य निष्पादन

	जन. 00-दिसं. 00	जन. 01-दिसं.,01	जन. 02-दिसं. 02 (जांच अवधि)
मी.ट.	****	****	****
सूचीबद्ध	100	41	85
वर्ष दर वर्ष की प्रवृत्ति		-59%	106%

64. क्षति के खतरे और कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

प्रकटन विवरण जारी होने के बाद विभिन्न हितबद्ध पार्टियों ने इस मापदंड पर टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि पाटनरोधी करार के 3.7 में उल्लिखित कारकों का अलग से विश्लेषण करने की जरूरत है ताकि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर संभावित प्रभावों के बारे में मत बनाया जा

सके । तथापि, अन्य हितबद्ध पार्टियों ने यह टिप्पणियां की हैं कि या तो क्षति का आरोप हो सकता है या क्षति के खतरे का आरोप क्योंकि आपस में अलग-अलग हैं । यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक क्षति के खतरे की स्थिति में घरेलू उद्योग की स्थिति के बारे में पर्याप्त सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे यह पता चल सके कि भावी आयातों से घरेलू उद्योग की स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन होने की संभावना है । यह भी बताया गया था कि क्षति के खतरे के मामले के लिए संगत उक्त सूचना वास्तविक क्षति के निर्धारण हेतु अपेक्षित सूचना से काफी अलग है । आगे यह कहा गया है कि समूचे घरेलू उद्योग पर लाभ स्तर, बाजार हिस्से निवेश पर आय, क्षमता उपयोग, वृद्धि आदि सहित उसकी स्थिति तथा आयातों के प्रभाव की संभावना का अनुमान लगाते हुए समग्र रुझानों को उपलब्ध कराने में आवेदक की विफलता को ध्यान में रखते हुए और उनकी विवरणियों तथा खुद की वृद्धि के बारे में वित्तीय विवरणों तथा आयातों से खतरे के अभाव के बारे में बिल्ट/बी जी पी एल द्वारा दिये गये स्पष्ट विवरण को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति के किसी खतरे की संभावना का कोई उचित आधार नहीं है ।

65. प्राधिकारी ने उपर्युक्तानुसार और प्रकटन विवरण के बाद उनके अनुरोधों के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पार्टियों के तर्कों की जांच की है । यह नोट किया जाता है कि आवेदक क्षति संबंधी मापदंडों के बारे में नवीनतम सूचना तथा अन्य ब्यौरों को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं ताकि प्राधिकारी क्षति के खतरे के निर्धारण में संभावित भावी प्रभाव का विश्लेषण कर सकें । तथापि, प्राधिकारी ने वास्तविक क्षति के खतरे से घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए ए डी ए के 3.7 में उल्लिखित मापदंडों की जांच की है । ई यू से एकमात्र सहयोगी निर्यातक और इंडोनेशिया के सिनार मैस ग्रुप के सत्यापन के बाद यह माना जाता है कि इन निर्यातकों के पास संबद्ध वस्तुओं की काफी अधिक निपटान क्षमता नहीं है । (ई यू में

क्षति उपयोग का स्तर लगभग 90% से 97% के बीच है जबकि इंडोनेशिया के लिए यह 75% से 95% के बीच है) प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में क्षति अवधि के दौरान अन्य देशों को हुए उनके निर्यातों में भारत को हुए निर्यातों की अपेक्षा अत्यधिक वृद्धि हुई है । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी द्वारा पूर्व के पैराग्राफों में यह माना गया है कि कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के रूप में कीमत प्रभाव पर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में विचार नहीं किया जाता है । हालांकि क्षति निर्धारण अवधि के दौरान कीमत में मामूली मंदी आयी है परंतु कीमत दबी नहीं रही है । इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य की दृष्टि से मूल्य में कमी को आसन्न नहीं समझा जा सकता जिससे घरेलू उद्योग की लाभकारिता प्रभावित हो सके । विचाराधीन उत्पाद की माल सूचियों के बारे में यह नोट किया जाता है कि इनमें क्षति निर्धारण अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और ये अधिकांशतः स्थिर हैं । वास्तविक क्षति के खतरे के घटक की जांच के बारे में यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 3.7 में उल्लिखित घटकों को छोड़कर अन्य घटक वास्तविक क्षति के निर्धारण से स्वयं अनिवार्य रूप से संगत हैं । यह भी नोट किया जाता है कि आयातों के परिणामी प्रभाव का विश्लेषण वास्तविक क्षति के खतरे के निर्धारण में आवश्यक है । प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि वास्तविक क्षति के खतरे का कोई निर्धारण करने में जांच प्राधिकारी को यह निष्कर्ष अवश्य निकालना चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने पर वास्तविक क्षति हो जाएगी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उब्ल्यू टी सी के पाटनरोधी करार से क्षति निर्धारण के खतरे के लिए कड़ी शर्तें लग जाती हैं जैसे कि यह तथ्य कि ऐसा निर्धारण केवल आरोप के तथ्य पर ही नहीं बल्कि अनुमान अथवा दूरगामी संभावना और परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे कि क्षति का होना स्पष्ट रूप से मालूम

हो और निकट हो, के आधार पर होना चाहिए । प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिए गए सभी तर्कों की जांच करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि भविष्य हाल के विगत से कैसे भिन्न होगा क्योंकि इस समय की वास्तविक क्षति न होने की स्थिति निकट भविष्य में उपायों की अनुपस्थिति में वास्तविक क्षति की स्थिति में कैसे परिवर्तित हो जाएगी । अतः उपर्युक्त की दृष्टि से प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है ।

निष्कर्ष:

66. प्राधिकारी उपर्युक्त पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

1. संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों से उनके सामान्य से कम मूल्य पर आयात किया गया है ।
2. तथापि, घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति का खतरा नहीं हुआ है ।

67. तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं करते हैं ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2004

FINAL FINDING

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of coated paper including paper and paper boards of 80 GSM and above originating in or exported from the European Union and Indonesia—Final finding

No. 14/7/2003-DGAD.—A. PROCEDURE :

1. The procedure described below has been followed:-

- (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from M/s. BILT Graphics papers Ltd, on behalf of the domestic industry, alleging dumping of coated paper including paper and paper boards of 80 GSM and above originating in or exported from the European Union and Indonesia (hereinafter also referred to as subject countries);
- (ii) The Authority notified the Embassies/High Commissions of subject countries in India about the receipt of fully documented application made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;
- (iii) The Authority issued a Public Notice dated 17th June 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of coated paper including paper and paper boards of 80 GSM and above in Schedule I of the Customs Tariff Act.
- (iv) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers, industry associations and to the complainant and gave them an opportunity to make their views known in writing.
- (v) According to sub-rule (3) and sub rule (4) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the application to all the known exporters and Embassies/High Commissions of subject countries in India. The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the known exporters from subject countries and importers from India. M/s Sappi Europe, Brussels European Union, and M/s Pindo Deli (PD) and

M/s Tjiwi Kimia (TK) of the Sinar Mas Group, Indonesia, have responded to the application by submitting substantial data and submitted the appendices to the exporters questionnaire and also offered verification to the data submitted by them. M/s Stora Enso, M/s M-Real Corporation and M/s UPM from the EU also submitted some of the information. However, since their information was considered substantially deficient, no verification of the data submitted by them was undertaken by the Authority and they have been treated as non cooperative in the subject investigation.

(vi) The Embassies/High Commissions of subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;

(vii) The questionnaire was sent to the large number of importers. Few importers have submitted the data as required in the form and manner as prescribed in the exporter's questionnaire. However many of the importers and users have submitted arguments which have been analysed to the extent as they have been found to be relevant to the investigation. The importers and users whose views have been taken into account amongst others include

Names of users and importers:

1. All India Federation of Master Printers, New Delhi
2. All India Paper Coaters' Association, Mumbai
3. ITC Bhadrachalam Paper Board Ltd, Andhra Pradesh
4. Shri Krishna Paper Mills, New Delhi
5. Pragati Offset Pvt Ltd, Hyderabad
6. Ajanta Offset, New Delhi
7. India Today, New Delhi
8. Thomson Press, Faridabad
9. Ankit Packaging Ltd, Hyderabad
10. Pitamber Coated Papers, New Delhi
11. Hero Paper Co, Mumbai
12. Rollatainers, Faridabad
13. Kosmo Graphics, Mumbai
14. Laxmi Traders, Kolkata

15. ITC Ltd, Kolkata
16. Ganapati Enterprises
17. Shyam Traders, Delhi
18. Sumat Prasad & Sons, Delhi
19. Indu Marketing Corporation, New Delhi

Exporters

1. M/s. Mayr-Meinhof-Karton, Austria
2. M/s. M-Real Corporation, Finland
3. M/s. Stora Enso Fine Paper, Netherlands
4. M/s. UPM-Kymmene Corporation, Finland
5. M/s. Sappi Fine Paper Europe, Belgium
6. M/s. Asia Pulp & Paper, Indonesia
7. M/s. P.T. Pindo Deli, Indonesia
8. M/s. P.T Tjwi Kimia, Indonesia
9. M/s. Prabrik Kertas, Indonesia
- 10.

Their views essentially pertain to the issue of the standing, domestic industry, product under consideration, like article and injury to the domestic industry. Their arguments have been analysed in the relevant headings and the determination of the authority with regards to claims of the various interested parties has been concluded in the same headings.

(viii) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;

(ix) **** in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

(x) The investigation of dumping and injury covered the period from 1st January 2002 to 31st December 2002 (Also called the period of investigation or POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from 1st January 2000 to the end of the POI (also called period under consideration or injury period). The import data has been examined from IBIS, Mumbai, DGCIS and data submitted by the exporters and importers. However after examining all

the data including the transaction wise data from DGCIS and IBIS, Mumbai, it was considered appropriate to rely on the information submitted by the exporters, importers, and transaction wise data from the IBIS (international business information system), Mumbai as DGCIS data does not show the exclusive classification with respect to the subject goods.

(xi) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 4th September 2003. All parties presenting views orally were requested to file written submissions, of the views expressed orally. Domestic verification as well as exporter's verification of the data submitted by them was undertaken by the Authority. The Authority sought and verified all the information it deemed necessary for the purpose of final Findings with regards to determination of dumping and resulting injury. The Authority conducted on the spot investigation of the domestic industry to the extent considered necessary. The Authority also carried out an on spot verification of the data submitted by cooperating exporters, namely, M/s Sinar Mas Group, Indonesia and M/s Sappi Europe, Brussels and verified the data submitted by them.

(xii) The cost of the production of the domestic industry was also analysed to work out the best cost of the production and the cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles based on the information furnished by the petitioner so as to ascertain if anti Dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry. In accordance with Rule 16 of The Rule supra, the essential facts/ basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 29th November 2004 and comments received on the same considered relevant to investigation are duly considered in Final Findings.

B PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product under consideration in the present investigation as mentioned in the initiation notification is Coated Paper including paper and paper board of 80 GSM and above. The product under consideration is classifiable within Customs Heading 4810 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.

3. It has been argued by some of the interested parties that the product under consideration also covers coated papers other than those meant for printing, writing and graphics purposes as the product under consideration in the initiation notification indicates

the customs Heading as 4810. It has also been argued that the product under consideration includes all the coated papers including packaging boards and other coated boards used for different purposes other than mentioned in the initiation notification and the description mentioned in the application. Some interested parties have also argued the fact that the Authority has rightly chosen the product under consideration regardless of the manufacturing process which was claimed by the applicant in their application. All the contentions have been carefully examined by the Authority. It is noted that anti-dumping investigation are carried out on the basis of description of the product under consideration and not its Tariff Classification. Moreover, in the initiation notification, it has been specifically indicated that the Customs Tariff classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. The Customs classification is only for the ease of reference and for collection of import data, and does not have any bearing on the product under consideration.

4 The Domestic Industry mentioned in their application that the Coated papers including papers and paperboards of 80 GSM and above are produced by applying a thin film of a formulation of chemicals containing various pigments, binders etc. It was also added by them that the coating process is used for improving the print gloss and smoothness of the printing papers. The process of coating is mainly done by two processes namely, Air Knife Coating and Blade Coating. The applicant produces the coated paper by adopting the Blade Coating technology which ensures that the finished paper so produced has the desired level of smoothness, finish, uniformity of coating and better printability as compared to coated paper produced from Air Knife Coating Technique. The coated paper produced by Blade Coated technology has a high IGT value which can be used for high speed printing. On the other hand, coated paper produced by Air Knife technology has a low IGT value which does not give the same printing speed. The Domestic Industry further contended that the paper imported from the subject countries is produced by Blade Coated technology with high IGT value and, therefore, directly substitutes the paper produced by the Domestic Industry. They also submitted that the present Petition was filed only against Coated Paper produced from Blade Coated technique since such products directly compete with the dumped imports from the subject countries.

5. It has also been argued by other interested parties that the process of manufacture cannot be a factor to define the product under consideration in an anti-dumping investigation. The Authority has carefully examined various submissions made by the

exporters, importers, and other interested parties as well as the Domestic Industry. The process of manufacture and the technical details of the product imported from the subject countries and those manufactured by the Domestic Industry were also physically verified by the Authority. The detailed technical specifications and the technical and commercial differences between the Blade Coated and Air Knife papers have also been examined. Based on the above input from all the interested parties including the Domestic Industry and cooperating exporters from the subject countries whose premises including their factories and information were physically verified by the investigation teams, the Authority is of the view that coated paper being imported from the subject countries are largely made through the blade coating technologies as the air knife coating techniques have not been in vogue in the recent years (it has been largely replaced by the Blade coated Process).. However, the Authority does not agree with the subsequent views of the domestic industry that the scope of the product should be restricted only to the product manufactured by blade process as it notes that the scope of the product can not be restricted by the process of the coating even if that given coating process gives the product a certain advantage in terms of properties like glossiness, IGT values and superior quality. Subsequent to the disclosure statement, various interested parties have reiterated their positions as mentioned in the disclosure statement and no fresh submissions/facts have been brought to the notice of the authority. Considering all the above factors the Authority considers the product under consideration as mentioned in the initiation notification as "coated paper including paper and paperboards of 80 GSM and above" (herein after also referred to as subject goods). The subject goods does not include coated paper with below 80 GSM (commonly known as light weight coated paper), glazed newsprint and all uncoated papers.

LIKE ARTICLE

6. The applicant claimed that under Rule 2(d), "like article" is defined as an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India. It is their contention that it is only in the absence of such an article that other goods which may not be identical but have characteristics closely resembling the dumped article, can be considered as "Like Articles". According to the petitioners, in the instant case, the dumping of Blade Coated paper is taking place as it is only this variety of coated paper which is produced abroad with very little or negligible quantities of Air Knife paper. It had also been submitted that besides the difference in processes of manufacture, the

resulting end product have characteristics vastly different from each other. Therefore they submitted that it would not be legally permissible to include the producers of Air Knife paper within the definition of "Domestic Industry" as per the Anti-dumping Rules. It is their claim that they constitute more than 95% of the domestic production of the "Like Article" i.e., Coated Paper including paper and paperboards of 80 GSM and above of Blade coating variety. In support of their contention, the Petitioners have placed reliance on CESTAT decision passed in the case of Birla Periclase Vs. Designated Authority reported at 2000(16) ELT 336 (Tribunal) wherein it has been held that the Designated Authority is permitted to take recourse to the second limb of the definition of "Like Article" only in the absence of an identical article as envisaged in the first limb of the definition.

7. Some of the importers and exporters have argued that the Coated paper produced through Air Knife Coating and Blade Coated technology could definitely be grouped as like article. It has been argued that the process of manufacture is not relevant for the determination of the "like article". The concerned exporter has cited the decisions of the Designated Authority in the case of 3,4,5-TMBA, 8 HQ and Magnesium from China. It is submitted that in all these cases the production process was not considered to be relevant for determination of the "like article". M/s. M-Real advanced similar arguments in the context of standing of the petitioners to file an anti-dumping application for and on behalf of the Domestic Industry.

The Authority has examined the submissions made by interested parties and has also examined the submissions of the domestic industry.

8. The Authority notes that Rule 2(d) defines like article as follows:

"(d) 'like article' means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;"

9. From the definition given above, it is clear that the Authority is required to consider that product as a "like article" which is identical or alike in all respects to the article under investigation. It is only in the absence of such an Article, that the Authority would be permitted to take resort to the second limb of the definition of "like article". It has been argued that the decisions cited by the exporters

may not be relevant as in these cases as the Authority resorted to the second limb of the definition when identical goods were not produced by the Domestic Industry, as envisaged under the first limb of the definition of "like article". The proposition by the exporters that the paper produced by Air Knife technology ought to have been included as "like article", was examined by the Authority. Following the representation by the exporters giving the names and addresses including their production capacities, the Authority called for the details of the production of the coated paper made through other processes by other producers as alleged by the other interested parties consisting largely of the exporters and importers. It is noted that several opportunities were given to the alleged other producers of the domestic like product to submit the information of their production, capacities and the fact if they are producing the like goods to the subject goods as alleged by the other interested parties. However, it is noted that the alleged other producers did not submit information as required in the proforma other than the production details of their plant for their period under consideration. As no information except the production details were forthcoming from the alleged other producers, the Authority has proceeded on the basis of the best information available to it.

10. For determination of the like article, the Authority is required to see whether various types are comparable in terms of parameters such as product specifications, physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, plant and equipment, functions and uses, their substitutability, tariff classification and consumer perception. The Authority also notes that technical specification of the subject goods produced and supplied by the applicants are identical/comparable to the goods imported from the subject countries and the two are comparable in terms of physical, chemical properties and substitutability in terms of its usage. Subsequent to the disclosure statement, various interested parties have reiterated their positions as mentioned in the disclosure statement and no fresh submissions/facts have been brought to the notice of the authority

11. Keeping in view the arguments made by various interested parties and the available material on record, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration.

STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY:

12. It has been argued by the some of the exporters and importers after the initiation that that the applicant does not have the standing to file the

application as per 5(3) of the Anti dumping rules. . The thrust of their argument is that the production of the "like article" by the Domestic Industry is less than the threshold limit of 25%. In support of their contention, M/s M-Real, one of the exporters of the subject goods from EU has relied upon a report from Jaakko Pöyry which has been obtained at their instance after the initiation of the investigation.

13. It is noted that the petitioners in their application had indicated that they accounted for more than 95% of the production of the "like article" in the country. The Authority had examined the production details as submitted by the applicant with regards to its obligation under 5(2) of the Anti dumping rules and had taken M/s BILT graphics paper as having the required standing to file the application in terms of the 5(3) of the Anti dumping rules as they constituted a major proportion of the domestic production under rule 2(b) to become a domestic industry read with rule 2(d). After the initiation notification, one of the exporters of the subject goods M/s M-Real from EU challenged the domestic industry status of the applicant in the Hon'ble Delhi High Court where their plea was treated as withdrawn. However, in the public hearing which was attended by most of the interested parties including the representative of the concerned ministry, and in the written submissions made before the Designated Authority after the public hearing, a plea was made to the Authority to ask the other alleged producers of the subject goods and to re-examine the standing of the applicant in the light of the information submitted by them. Though it was made known to them that a communication had already been made to the concerned ministry and its reply was awaited, the other interested parties submitted that the Authority should proactively ask so called other producers of the product concerned so that the standing of the domestic industry could be re ascertained by the Authority themselves before proceeding further in the investigation. They also requested the Authority not to proceed with the investigations till the standing issue is re-examined.

14. For the purpose of determining the standing of the petitioner to file the application on behalf of the Domestic Industry, it is to be seen that the petitioners should satisfy the conditions prescribed under Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules. The relevant Rules are reproduced as under:

" Rule 5(3): The designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless –

(a) it determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of

the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry:

Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty five per cent of the total production of the like article by the domestic industry, and

(b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding -

- (i) dumping,
- (ii) injury, where applicable; and
- (iii) where applicable, a causal link between such dumped imports and the alleged injury, to justify the initiation of an investigation.

Explanation. – For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application."

15. From the above, it is clear that the Authority is required to take into consideration the total production as well as the production of the petitioners only in so far as it relates to the "like article". Continuing with the examination of the submissions made by the other interested parties in the preceding paragraphs, the Authority notes that the submissions made by some of the exporters as well as importers are erroneous in as much as they have also included a large number of papers which are neither the product under consideration nor the "like article". As regards the tests being applied by the Designated Authority, it is noted that the Designated Authority came to the conclusion that the petitioners account for more than 95% of the production of the Blade Coated paper (the "like article") in the country. It may also be mentioned that the Authority, as a matter of abundant precaution, also obtained the figures of all coated papers including papers and paperboards irrespective of the process of coating prior to the initiation of investigations. It was observed by the Authority that the petitioners accounted for more than 50% of the total domestic production (for coated papers including paper and paperboards irrespective of the processes). Thus, viewed from that perspective, the Authority had examined and satisfied itself that the petitioners fulfilled the criteria of standing as set out in Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.

16. Subsequent to the public hearing, the Authority also obtained the information from CPPRI, which clarified that the production of the subject goods was 252728 MT, during the period of investigation. In fact, a letter

dated 2nd September 2003 of Jaakko Pöyry also states that the total production of coated paper (both from air-knife and blade coated technology) is 240000 MT. However, the report submitted by the concerned ministry are inconclusive in the sense that not all the queries addressed by the other interested parties have been addressed. However, in a response to the letters addressed by the Authority to all the other alleged producers of the product concerned, their association namely M/s All India Paper coater's association in their letter have written to the Authority that the total production of the subject goods are 156886MT and they support the application filed by M/s BILT Graphics papers Ltd for imposition of anti dumping duty from dumped imports from EU and Indonesia. With this production figure, the applicant constitutes the domestic industry within the meaning of the rule 2(b) read with rule 2(d) and thus they have the standing to file the application as per the 5(3) of the Anti dumping rules. Subsequent to the disclosure statement, there are arguments that M/s BILT Graphics Ltd has no legal meaning as it has ceased to be in effect since 2002 after its merger with M/s Ballarpur Industries Ltd and thus injury analysis of the domestic industry needs be to be revised. The Authority notes that M/s BILT Graphics paper Ltd, the original applicant in this instant case was formally amalgamated with the M/s Ballarpur Industries Ltd under a scheme of amalgamation and arrangement between the two in terms of companies act. The scheme was approved by the Delhi high court on 27th march 2003 and by Mumbai high court on 10th April 2003. Statutory return was filed with ROC Mumbai on 29th may 2003 and ROC Mumbai on 19th June 2003. Subsequently, the domestic industry supplied the copies of these orders along with the merger scheme (affected from an earlier date) to the Authority. It is observed that the standing of the applicant to file an application for an anti dumping application for imposition of anti dumping duties is dependent upon the production of like articles in the India during the POI. Therefore, subsequent amalgamation on the basis of the high court order does not have any bearing on standing of the domestic industry. With regard to the arguments submitted by interested parties about exclusion of ITC Ltd from the purview of the domestic industry, it is stated that no reply with regard to their production details or their affiliation with the exporter has been received by the authority despite several reminders to them.

17. In view of the above, the Authority holds that the applicant qualifies as "Domestic Industry" accounting for a major proportion of the domestic production during the period of investigation and satisfies the criteria of standing as envisaged under Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.

Methodology and Assessment of Dumping

F. Dumping.

18. Under Section 9A(1) I of the Customs Tariff Act 1975, Normal value in relation to an article means:

1. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
2. When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-
 - a. Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - b. The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)";

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

19. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(i)(c). Only three producers, namely, M/s. Sappi Europe (Brussels) from EU and M/s TK and M/s PD (Indonesia) have responded to the questionnaire in the form and manner required as per letter to the exporters and exporter's questionnaire.

(a) Cooperation

20. M/s. Sappi Europe, EU has responded to the exporters' questionnaire by giving substantial information with regard to various appendices mentioned in the exporters' questionnaire. They also offered verification of the data submitted by them and the Authority has verified the data after onsite inspection at the premises of the producers and the exporter. Other exporters namely M/s Stora Enso and M/s M real have responded to the initiation notification and also attended the public hearing but they have not responded to the information sought by the Authority in the form and manner as prescribed in the exporters' questionnaire. The Authority recalls that apart from the normal time schedule of 40 days from the date of initiation notification, further opportunity was given to these exporters to submit the information but they have not responded to the Authorities letter by submitting the required information. The authority notes that these companies were reminded by the authority to submit the complete response in the form and manner as prescribed in the exporter's questionnaire along with its Non confidential summary and was also reminded of the fact that if the information was not supplied within reasonable time, the Authority would be free to make determinations on the basis of the facts available including those contained in the application for the initiation of the investigation by the domestic industry. The Authority notes that none of the exporters and producers except M/s Sappi Europe (EU) have submitted response to the Authority letter asking for appendix wise information in the form and manner required in the exporters questionnaire. As the exporters from Indonesia namely M/s PD and M/s TK have submitted partial data which have been verified by the Authority, they are being treated as partially cooperative. In view of non-submission of response to the exporter's questionnaire, the Authority treats the rest of the producers and exporters as Non-cooperative within the meaning of Agreement of Anti Dumping and Anti dumping rules.

(b) Normal Value & Export Price for Sappi Europe, Brussels

21. (i) SAPPI Europe, Belgium has submitted a detailed response to the Exporter's Questionnaire. It has submitted information relating to all the sections of the questionnaire as well as the appendices 1,2,2A,2B,3,3A,3B,4,5,6,7,8A,8B and 9 as per new format. SAPPI has also furnished detailed audited financial statements for the financial years POI and two years prior to that. A perusal of the response indicates that SAPPI Europe has seven related companies that produce the product

concerned in Europe.

(ii) Domestic sales in Europe are handled by SAPPI Europe SA [hereinafter referred to as Sappi Europe]. SAPPI Europe gets orders from their customers in Europe. The orders are passed on to any of the seven producing mills depending upon the product, delivery schedule, availability, place of delivery, etc. The concerned mill supplies the goods to the customer but raises an internal invoice on SAPPI, Europe. Sappi Europe raises an invoice on the customer. In a sense, SAPPI Europe acts as an agent of the mills concerned.

(iii) Export sales to India are handled by the Hong Kong branch of another related company M/s. SAPPI Paper Holding GmbH. The Hong Kong Branch of SAPPI Paper Holding GmbH collects orders from customers and passes it on to the concerned mills. The mill supplies the goods directly to the customer in India and raises an internal invoice on SAPPI Paper Holding, Hong Kong Branch which in turn raises its invoice on the customers located in India.

(iv) SAPPI has submitted sample copies of domestic sale invoices made by SAPPI Europe SA as well as export sales invoices made by SAPPI Holding AG, Hong Kong. Documents for domestic sale include order confirmations, invoices and weight list. The documents for export sales include order confirmations, commercial invoices, weight list, quantity/quality inspection certificates, certificate of marine insurance, shipping bills and certificate of origin.

(v) Appendix-I: Information relating to Home Market Sales in EU contains **** records. As an MS Excel file can handle only a maximum of 65,536 records, this appendix is too big for MS Excel. Therefore, SAPPI has given the file in MS Access format. A summary of this Appendix was prepared using MS Access. The summary report gives product code-wise details of domestic sales. The key parameters of the summary report are given in the confidential enclosures.

(vi) Similarly, SAPPI has submitted Appenx-2: Exports to India in MS Access format. A summary report was made using MS Access. Key parameters of the file are given below:

- i. Export sales to India consist of **** records;
- ii. Material exported to India fall under **** different product codes;
- iii. Total quantity exported to India was **** MTs.
- iv. Net invoice value was Euros. ****
- v. Ex-factory realisation was Euros. ****
- vi. Weighted average ex-factory export price to India was

Euros. **** per MT.

- (vii) Both the above mentioned summary reports were converted into a MS Excel file named 'SAPPI Analysis.xls'. All other appendices have been given in Ms EXCEL Format.
- (viii) Appendix-2A gives 'Monthly sales overview' of domestic sales and export sales to India for the years 2001, 2002 and up to September 2003. The totals as per monthly sales overview was cross checked with the details given in Appendix 1 and 2.
- (ix) SAPPI has furnished Appendix-3A : Sale Price structure for exports to India. They have claimed deductions towards credit cost, rebates, commission, freight and insurance. The net ex-factory export price comes to Euros. **** per MT. In Appendix - 3B: Sale Price structure for domestic sales, SAPPI has claimed deductions towards discounts, rebates, commission, freight and insurance from the domestic sales. The ex-factory domestic sale realisation comes to Euros. **** per MT. The net ex-factory export price to India shown in Appx-3A and the ex-factory domestic selling price shown in Appx-3B tally with Appx-2 and Appx-1 respectively.
- (x) In Appx-4 SAPPI has furnished capacity, production and sales for SAPPI as a whole. In Appx-5 SAPPI has furnished statement of raw materials and packing materials consumption. In Appx-6 SAPPI has provided all costs relating to figures for the product-types that have been exported to India as also sold in Europe.
- (xi) In Appx-7 SAPPI has furnished the allocation and apportionment of expenditure for the total operations of the company for the year 2002, Share applicable to the product under investigation and share applicable to other products. SAPPI has furnished in Appx-8A : Factory cost and profits of Exports to India in respect of product-types that have been exported to India. Similarly, SAPPI has also furnished Appx-8B :
- (xii) Normal value was determined for each product description sold in EU domestic market following the Anti dumping rules and article 2 of the ADA. There were only **** product-descriptions that had been exported to India. In respect of all the **** product-descriptions, it was found that less than 20% of the domestic sales were below COP. Therefore, normal value was determined in respect of all the **** product-descriptions.
- (xiii) Further, the Authority also verified the adjustment factors in the export sales to India and also their sales in the domestic market. As regards adjustment factors in export sales to India, the authority verified

from their records whether all adjustments claimed by them and verified by the Authority are deducted from the export price.

(xiv). The dumping margin calculation was revised after verifying the data from the exporters with regards to their normal value and export price at the ex factory level and after verifying all the adjustments. The calculations pertaining to the determination of normal value and export price are annexed at the Confidential Disclosure.

Other exporters from EU:

22. As the volume of exports to India from exporters other than the co-operating exporter was very high as compared to total volume of import from EU as a whole, residual dumping margin is determined for the residual exporters by taking the normal value as per the facts available under rule 6(8) and export price as per their exports to India. Subsequent to the disclosure statement, the domestic industry has argued that the export price for the other exporters from the European Union should be taken from the DGCI&S data. It has also been argued in the response to the disclosure statement that export price for the injury determination on the domestic industry should be determined in accordance with the DGCI&S data. The authority has examined the contentions of the various interested parties with regard to computation of export price for other exporters from EU. It has been noted by the authority that the subject investigation was initiated with the import data made available to the authority from the transaction wise data of IBIS for the POI and two years prior to that. It was then contended by the applicant that as the classification of the product under consideration was not exclusive in the six or eight digit customs head and keeping in view the product under consideration, it had not been feasible to rely on the summary classification of the DGCI&S. Subsequent to the initiation, the authority called for transaction wise data from DGCI&S. However, after examining the transaction wise data, it became apparent that the subject imports are reported in many classifications and the data culled out from the transaction wise information was considered understated for the product under consideration when examined in the light of actual import data submitted by the responding exporters. As is the usual practice in the Directorate, the authority has accepted the export data submitted by the responding exporters i.e. M/s. Sappi (Europe), and M/s. Stora Enso for working out their export prices. However, since only M/s. Sappi Europe has submitted the complete information in the form and manner of the exporter's questionnaire, they have been declared cooperative exporters in the subject investigation. For the rest of the exporters, the export price has been determined as per the best available information with the authority.

Normal Value & Export Price for TK, Indonesia and PD Indonesia

23. The group in its entirety is called the Sinar Mas Group. The Sinar Mas group is then split into different business units. One of the business unit is M/s Pt. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia TBK (the company) which is controlled by ****, who is also company's majority shareholder. The other business unit of the firm is M/s Pindo Deli Pulp and Paper Mills (the company) which is controlled by **** through indirect equity investments. **** is the principal shareholder of ****, which is the company's majority shareholder. Following the submission of the substantial information from both these concerns, a verification visit was conducted by the verification team from the DGAD. It was verified that the raw material for the manufacture of Coated Paper & Paper Board is pulp which the sister concern of the company manufactures and the same is also sourced from outside also. The prices/transfer prices are set in USD. The company has claimed that they reflect international prices and the raw material prices are based on arm's length transactions.

(i) Pt. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia TBK. (TK)

(a) The consolidated financial statements of the company have been prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in Indonesia (Indonesia GAAP). The company generates monthly profit and loss account and production cost reports for its reporting purposes. The company has implemented ERP system for its operation and financial information system. M/s Pt. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (TK) provided the cost of production figures to the investigating team. The reporting year of the company is the calendar year which reconciles with the period of investigation. Appendices 7&8 require the information furnished to be certified by a practicing accountant which has not been provided by the company. It was verified that the total production of Coated Paper & Paper Board during the Period of Investigation was ****(capacity utilisation ****). Total sales during the period of investigation was ****. The company has submitted Appendices 7 and 8. The allocations for raw material, spare parts, utilities and direct labour have been done on actuals. Manufacturing overheads have been apportioned on production quantities. Administrative overheads and selling and distribution costs have been allocated on sales amounts. From 2001, the company and certain subsidiaries have defaulted on various principal and interest payments on loans and are in technical default on other loans. The company had a net loss of US\$**** million for ended December 31, 2002. On March 12, 2001 The company and **** announced a standstill on payment of all obligations (principal and interest) due to their creditors, except for

some. Subsequent to the announced standstill, the company began negotiating terms for a consensual debt restructuring. The company has since signed master restructuring Agreements. This MRA and other restructuring documents constitute the definitive restructuring agreement. The success of this MRA is dependent on a host of factors which have been outlined in the financial statements. However, for the purpose of allocating financial expenses (including exchange losses) for this investigation, the company has gone ahead with the presumption that the MRA has been successfully implemented and have restated their liabilities and expenses accordingly. In Appendix 7 the company has claimed financial expense as US \$ **** million USD instead of the financial statements amount of **** million USD (for the calendar year 2002). The company claims that the terms contemplated under MRA are bound to be implemented and as such they have recalculated their payables in terms of that agreement. The verification team pointed out that the success of the master restructuring agreement was dependent on a host of factors (significantly undeterminable and not in the control of the company). Also till the time of verification no proof has been provided of the restructuring becoming applicable. An adjustment in the amount of liabilities payable should be demonstrated in their audited accounts. In this particular case there has been no adjustment even a year later. Subsequent to the issuance of verification report and disclosure statement, the exporter has argued that authorities treatment of its financial expenses and profit need to be revised in light of actual liabilities and they have submitted a revised agreement in their support. However, the Authority reiterates its method of determination of financial expenses and reasonable profit as per its earlier determination as intimated to the exporter.

(b) As per Article 2.2.1.1, for determining the cost of production as per Article 2.2, costs shall normally be calculated on the basis of the records kept by the exporter or producer under investigation provided that such records are in accordance with the generally accepted accounting principles (GAAP) of the exporting country. The published financial statements of the company have been certified to be as per the generally accepted accounting principles of the exporting country. In the face of available financial statement as per GAAP, the reliance of the company on subsequent development of MRA for allocation of interest expenses was not considered reasonable. Accordingly the total cost to make and sell has been revised. Details of the same are enclosed in the confidential verification reports as Annexure A, B and C. As the domestic selling price is below the cost of the production on the

weighted average basis during the POI, the ordinary course of trade test could not be conducted in the subject investigation and hence the normal value has been constructed by using the best information available under rule 6(8) of the ADA. The constructed normal value has been worked out after providing a profit margin of **** to the cost of production.

(ii) M/s Pindo Deli Pulp and Paper Mills , Indonesia

(a) The consolidated financial statements of the company and subsidiaries have been prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in Indonesia (Indonesia GAAP). This is an international standard that is used by majority of companies in Indonesia. The company generates monthly profit and loss account and production cost reports for its reporting purposes. The company has implemented SAP system for its operation and financial information system. M/s Pindo Deli provided the cost of production figures to the investigating team. The reporting year of the company is the calendar year which reconciles with the period of investigation. Appendices 7&8 requires the information furnished to be certified by a practicing accountant which has not been provided by the company. The total production of Coated Paper & Paper Board during the Period of Investigation was ****MT(capacity utilisation-****). Total sales during the period of investigation was **** MT. The company has submitted Appendices 7 and 8. The allocations for raw material, spare parts, utilities and direct labour have been done on actuals. Manufacturing overheads have been apportioned on production quantities. Administrative overheads and selling and distribution costs have been allocated on sales amounts. From 2001, the company and certain subsidiaries have defaulted on various principal and interest payments on loans and are in technical default on other loans. The company had a net loss of US\$ **** million and having a deficit of US\$ **** million for the year ended December 31, 2002. On March 12, 2001 **** and its subsidiaries which include the company and **** announced a standstill on payment of all obligations (principal and interest) due to their creditors, except for some. Subsequent to the announced standstill, APP began negotiating terms for a consensual debt restructuring. The company has since signed master restructuring Agreements. This MRA and other restructuring documents constitute the definitive restructuring agreement. The success of this MRA is dependent on a host of factors which have been outlined in the Consolidated financial statements. However, for the purpose of allocating financial expenses (including exchange losses) for this investigation, the company has gone ahead with the presumption

that the MRA has been successfully implemented and have restated their liabilities and expenses accordingly. In Appendix 7 the company has claimed financial expense as US \$ **** million USD instead of the financial statements amount of **** million USD (for the calendar year 2002). The company claims that the terms contemplated under MRA are bound to be implemented and as such they have recalculated their payables in terms of that agreement.

(b) The verification team noted after examining all the documents that the success of the master restructuring agreement was dependent on a host of factors (significantly undeterminable and not in the control of the company). Also till the time of verification no proof has been provided of the restructuring becoming applicable. An adjustment in the amount of liabilities payable should be demonstrated in their audited accounts. In this particular case there has been no adjustment even a year later. Subsequent to the issuance of verification report and disclosure statement, the exporter has argued that authorities treatment of its financial expenses and profit need to be revised in light of actual liabilities and they have submitted a revised agreement in their support. However, the Authority reiterates its method of determination of financial expenses and reasonable profit as per its earlier determination

(c) As per Article 2.2.1.1, for determining the cost of production as per Article 2.2, costs shall normally be calculated on the basis of the records kept by the exporter or producer under investigation provided that such records are in accordance with the generally accepted accounting principles (GAAP) of the exporting country. The published financial statements of the company have been certified to be as per the generally accepted accounting principles of the exporting country. In the face of available financial statement as per GAAP, the reliance of the company on subsequent development of MRA for allocation of interest expenses was not considered reasonable. Accordingly the total cost to make and sell has been revised. Details of the same are enclosed as Annexure A, B and C. The constructed normal value has been worked out after providing a profit margin of 5%. As the domestic selling price is below the cost of the production on the weighted average basis during the POI, the ordinary course of trade test cannot be conducted in the subject investigation and hence the normal value has been constructed by using the best information available under rule 6(8) of the ADA. The constructed normal value has been worked out after providing a profit margin of 5% to the cost of production. Subsequent to the disclosure statement, it has

been pointed out by the domestic industry that the authority should have accepted the export price as per the DGCI&S data. In this regard, it is noted that the subject investigation was initiated with the IBIS data (data from the customs daily list provided by IBIS and made available by the domestic industry). Subsequent to the initiation, the exporters who constitute the entire exports to India during the POI did not submit the volume and price of exports of subject goods to India. The authority, in view of this fact, has accepted the export price reported in the IBIS data at the time initiation and all the adjustments and all the adjustment have been carried out as per the best information available which is a usual practice in view of the non-cooperation of the exporters to furnish the export information to India.

Comparison

24. For the purpose of a fair comparison between the normal value and export price at an ex factory level, due allowance in the form of adjustments was made for differences that were claimed and demonstrated to affect prices and price comparability. These adjustments were made, wherever appropriate, in respect of transport, insurance, handling, loading, credit costs and others in accordance with para 6 of the annexure I of the anti dumping rules made under the Customs Tariff Act.

Dumping Margin for TK and PD, Indonesia:

25. In accordance with Rule 6(iv) of annexure I to the anti dumping rules, the dumping margin was established on the basis of constructed normal values with the weighted average export price. The comparison showed the existence of dumping of the subject goods by the exporters during the POI. The weighted average dumping margin, expressed, as a percentage to the export price has been determined and is positive for both the exporters.

Other exporters from Indonesia:

26. As the volume of imports from TK and PD was very high (In fact all the exports made from Indonesia were from these two exporters only during the POI) as compared to total volume of import from Indonesia as a whole, residual import margin is determined for the residual exporters as determined for M/s Pindo Deli, Indonesia.

Dumping Margin:

27. Dumping Margin

Country	Name of the Producer/exporter	Normal value	Export Price	D.M%
EU	M/s Sappi Europe	****	****	24
	All Other Producers/exporters	****	****	35
Indonesia	Pindo Deli	****	****	44.2
	TK	****	****	33.5
	Others	****	****	44.2

G. Injury

a) Domestic consumption/demand

28. The domestic consumption/demand is based on the sales of the Domestic Industry, imports from the subject countries and imports from other countries into India. On this basis, the domestic demand or consumption of the subject goods in the domestic market increased from 83194 MT in Jan-Dec 2000 to 110721 MT in the period of investigation representing an increase of 33%. It can be seen that the total demand in the country is constantly growing on a year-to-year basis also.

Domestic demand/consumption			
	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
Demand (MT)	83194	90597	110721
Indexed	100.00	108.90	133.09

29. (a) Cumulative Assessment of the effects of imports concerned

- i) The Authority examined whether imports of subject goods originating in EU and Indonesia should be assessed cumulatively as per Article 3.3 of the Agreement on Anti-Dumping and Rule 11 of the Anti Dumping Rules Under the Customs Tariff Act.
- ii) The margin of dumping established in relation to the imports from each of the subject countries (EU and Indonesia) was above the de minimus threshold as defined in Article 5.8 of the Agreement on Anti-Dumping and Rule 14 of the Anti Dumping Rules and Volume of dumped imports from each of these countries was not negligible.
- iii) The domestic product and product supplied by producers in various countries are like articles; and the imported products and domestically produced subject goods can and are being interchangeably used. Response filed by the various interested parties and correlation of the same with customer wise sales of the domestic industry makes it evident that there are a number of parties who have resorted to purchase from the domestic industry and imports from subject countries. It is further noted that subject goods supplied by various countries compete in the same market. Further, it is also noted that products supplied by various producers in subject countries are being marketed in India during the same periods through comparable sales channels and under similar commercial conditions.
- iv) In the light of the above, the authority has considered that the criteria set out in article 3.3 of the Agreement of Anti-Dumping and as per para iii of the Annexure II under Rule 11 were met with respect to imports from EU and Indonesia and therefore imports from these two countries should be cumulated for the purpose of injury determinations.

b) Imports originating in the subject countries.Volume

30. The absolute volume of dumped imports of the product under consideration from subject countries into the domestic market increased by 140 % over the period under consideration. As a share in total demand, it increased by 81%. The authority further notes that the domestic consumption increased by 33% during the period under consideration. It is therefore concluded that there has been steady and significant increase in demand and also the volume of dumped imports has significantly increased over the period under consideration.

Share of Imports from subject countries in Total imports			
	Jan 00- Dec 00	Jan 01- Dec 01	Jan 02- Dec 02(POI)
European Union (MT)	10027	15962	24323
Indonesia (MT)	4057	2750	9592
Total Imports from subject countries (MT)	14084	18712	33914
Other Countries (MT)	5413	3059	3043
Other countries share	27.76%	14.05%	8.23%
Total Imports (MT)	19496	21771	36957

(c) Share of subject countries in total imports

31. Over the period under consideration, the share of the dumped imports from the subject countries in the total imports increased by 27% percentage points. The market share held by the dumped imports in the total imports increased from 72% in 2000 to 91% during the POI. It is therefore noted that the share of dumped imports has increased significantly in the share of the total imports.

Share of Imports from subject countries in Total imports			
	Jan 00-Dec 00	Jan 01- Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
European Union (MT)	10027	15962	24323
Market Share	51.43%	73.32%	65.81%

Indonesia (MT)	4057	2750	9592
Market Share	20.81%	12.63%	25.95%
Total Imports from subject countries (MT)	14084	18712	33914
Total market share of dumped imports from subject countries	72.24%	85.95%	91.77%
Other Countries (MT)	5413	3059	3043
Other countries share	27.76%	14.05%	8.23%
Total Imports (MT)	19496	21771	36957

32. On the basis of above examination, it is concluded that there has been a significant rise in the market share of dumped imports of the subject countries as a share of total demand and it has increased significantly during the POI as compared to previous years.

(d) Prices

Evolution of Price over the period under consideration

33. Between 2001-02 and the POI, the average CIF prices of the imports originated in subject countries decreased by 10.75% percentage points during the period under consideration or injury period.

	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
CIF Price of Dumped Imports (Rs/MT)	38967	33782	34779
Indexed	100.00	86.69	89.25
Domestic Prices (Rs./MT)	****	****	****
Indexed	100.00	97.63	96.01

(e) Price Undercutting (PUC).

34. A comparison for comparable types of the product concerned was made between the exporting producers and the domestic industries average selling price in the domestic market, net of all rebates and taxes to unrelated customers, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex factory level. The CIF

import prices of the subject countries concerned were adjusted for post importation basic customs duties. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in the subject countries were sold in the domestic market at prices which did not undercut the domestic industry's prices when expressed as a percentage of the domestic selling prices of the domestic industry. In fact, the margin of price undercutting was significantly negative with respect to the imports originating in or exported from EU while it was marginally positive with respect to the subject goods originating in or exported from Indonesia. However, it was significantly negative when both the exporting countries are cumulated. Subsequent to the issuance of the disclosure statement, it has been argued that the price undercutting should have been calculated in the cumulative way and not for the subject countries individually. It is noted by the authority that the price undercutting has been shown individually as well as cumulatively.

PUC and Injury Margin (Rs /MT)			
	EU	All Subject countries	Indonesia
CIF Price	35947.98	34778.94	31758.92
landed Value	47199.70	45664.75	41699.46
Selling Price	****	****	****
Price Undercutting	****	***	****
Price Undercutting Percentage range	(10-15)	(8-12)	0-1

(f) Price Underselling (PUS)

35. The Authority has also examined the claim of the petitioner that the domestic industry is suffering on account of the decline in the profitability from the sale of subject goods. The Authority notes that price underselling is an important indicator to make an assessment of the injury. The Authority has worked out the Non-injurious price for the product under consideration and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The analysis shows a insignificant level of incidence of price underselling causing injury to the domestic industry when cumulated. In response to the submissions made by interested parties subsequent to the disclosure statement, it is stated that the price underselling (Injury Margin) has also been determined cumulatively for all subject countries together as well as for subject countries individually.

PUS and Injury Margin Rs/MT			
	EU	All Subject countries	Indonesia
CIF Price	35947.98	34778.94	31758.92
Landed Value	****	****	****
Selling Price	****	****	****
Non Injurious Price	****	****	****
Injury Margin	(-)	****	****
Injury Margin range	(0.5-2.0)	3-5%	10-13%

(g) Price Depression

36. As noted in the preceding paragraph, selling prices of the domestic industry have marginally declined during the POI as compared to 2000-01. The Authority on the basis of the examination concludes that the domestic industry is facing an insignificant price depression on account of the dumped imports from subject countries

Domestic Prices (Rs./MT)	****	****	****
Indexed	100.00	97.63	96.01

(h) Situation of the Domestic Industry

Preliminary remarks

37. As per paragraph (iv) of Annexure II to the Anti-dumping Rules, the examination of the dumped imports on the Domestic Industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various interested parties have submitted the arguments that there is no material injury to the domestic industry during the period of investigation (POI). It has also been pointed out by various interested parties that the authority is bound to examine whether there is a continuing threat of dumping and causal link to the injury and the authority

must examine any and all the relevant information, in this regard, independently of dumping margin determination. It has also been submitted that there is no threat of imports at dumped prices or below the non injurious price claimed by the domestic industry and consequently, there is no threat of continuing injury. Many of the interested parties have cited the reports appearing in the website of the domestic industry in India and have pointed out that this information present a rosy picture of the present and likely future market conditions in India. The interested parties comprising of exporters and importers have argued that most of the injury parameters as enshrined in the 3.4 of the antidumping agreement do not reflect any injury to the domestic industry. However, the domestic industry has maintained that they have suffered injury on account of declining market share, profitability, ROI and on account of volume effect of dumped imports. All the submissions made by the various Subsequent to the issue of the disclosure statement, the domestic industry has maintained that various injury parameters as per 3.4 of the ADA do show varying degree of injury to the domestic industry and they have enclosed some jurisprudence in this matter. On the other hand, various exporters have maintained that there is no price effect on account of increased import volumes from subject countries and 15 parameters showing consequent impact to the domestic industry do not show injury to the domestic industry as many of the parameters show negative determinations. With regard to arguments pertaining to the determination of the Non injurious price (NIP) of the domestic industry, it is stated that NIP has been based on the actual cost of production and other technical parameters of the domestic industry and a reasonable return has been added to arrive at the NIP. All the submissions made by the various interested parties have been analysed in terms of various indicators as mentioned in the 3.4 of the ADA which are as follows.

(a) Production, Capacity and Capacity Utilization

38. It can be seen from the following table that the production of the Domestic Industry dropped by 2.6% during the year Jan 2001-Dec 2001 as compared to the year Jan-Dec 2000 while there is a negligible improvement during the period of investigation but the same is still less as compared to the base year. There has been no increase in the production capacity of the Domestic Industry during the period under consideration. Further, it may also be noted that the capacity utilization of the Domestic Industry has declined marginally by 2.15% during the period of investigation as compared to the year Jan-Dec 2000. It has been contended by the interested parties that a decline of capacity utilization of even the above magnitude constitutes injury to domestic industry in scenario of increasing demand. However, the authority notes that the capacity utilization of the domestic industry continues at a significantly high level during the injury determination period. Further, there has not been any capacity creation during the same period by the domestic

industry even after the demand has increased significantly. On the basis of above, it is concluded that the domestic industry was not affected adversely on account of this parameter.

Capacity, Production and Capacity Utilisation (Coated including uncoated papers and paperboards)			
	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
Capacity(MT)	115000	115000	115000
Production(MT)	104810	101817	102336
Capacity Utilisation%	91.14	88.54	88.99

(b) Sales Volumes

39. It may be seen from the following table that there has been a slight increase in the sales volume of the domestic industry in the period of investigation as compared to the preceding year. However, it has to be seen that the Domestic Industry has been able to retain its sales volume only by marginally reducing the prices as the Domestic Industry could not afford to lose its customers. It may be seen that the total demand/consumption has increased by 33 % (27527MT) during the injury period whereas petitioner's sales volume increased by a moderate 9% (5997 MT only) during the same period. It has been argued by the domestic industry that increase in the sales volume could not be considered as appropriate given the fact the demand has increased by 33% in the same period. It is again reiterated by the authority that sales volume could not have been increased given the fact that no capacity addition was made by the domestic industry during the injury determination period and thus, their production could not have catered to the domestic demand even without the dumped imports from subject countries. Further, It is also noted that the domestic industry is having significant exports in addition to the domestic sales. Thus, in view of the above, the authority does not conclude any injury on account this parameter.

Year	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
Sales	****	****	****
Trend	100.00	108.05	109.41

(c) Sales Prices

40. It may be seen from the table below that the selling prices of the domestic industry has consistently been declining. However, the decline in the sales price has been very marginal and is in keeping with the decline in the cost of the production of the domestic industry. In view of the fact

that there has been little decline in the sale price during the injury determination period, it could be concluded that the domestic industry did not get injured significantly on account of this parameter.

	Jan 00	00-Dec 01	Jan 01	01-Dec 02(POI)	02-Dec
Rs./MT		****		****	****
Indexed		100		98	96
COP/MT		****		****	****
Index		100		95.19	95.84

Domestic Industry's Sales prices

(d) Market share

The table below shows that the market share of petitioner has declined from 76% in POI to 62% during the period of injury. Over the same period, market share of the dumped imports has increased from 16% to 30%. It may also be noted that the total market in India has grown by 33% during the period of injury. Further to the disclosure statement, it has been argued that decline in the market share of the domestic industry should have been taken as a sure evidence of injury as is commonly followed in other countries. The domestic industry has also cited various jurisprudence in this matter along with the practice in the other countries. After considering contentions of the domestic industry, the authority notes that the decline in the market share could have been taken to be a firm determination of injury when the domestic industry would have the capacity to increase its market share in view of the rise in the demand. However, in the subject case, the domestic industry does not have the capacity to increase its production and sales volume even with high capacity utilization in view of the rising demand and hence, decline in the market share is a natural corollary of insufficient capacity of the domestic industry. In view of the above, it is noted that the decline in the market share could not be a factor for injury to the domestic industry in the subject investigation.

Market Share of Domestic Industry in demand			
	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
% Share held by			
Petitioner	76.57	75.97	62.95
Other Producers	0.00	0.00	3.67

Domestic Industry	76.57	75.97	66.62
Subject goods from subject countries goods	16.93	20.65	30.63
Other Imports	6.51	3.38	2.75

(e) Stocks

41. It may be seen that the stocks of the Domestic Industry has declined from 5227 MT in the year 2000 to 4767 MT in 2001 and then to 4445 MT in the POI. As compared to the year 2000, there has been a reduction of 8.8% in the year 2001 and during the POI it declined by 6.16%. It is considered that the domestic industry has not suffered injury on account of this parameter.

Actual and Potential Negative Effects on Inventories			
	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
Inventories/Stocks	****	****	****
Domestic Sales Volume Index	100	108	109
Production(MT)	****	****	****
Inventories /production	5.0	4.7	4.3
Inventory as % to Sales Volume	8.21	6.93	6.38
Indexed Stocks	100.00	91.20	85.04

(f) Profitability

42. The reduction in prices by the Domestic Industry to compete with the dumped imports appeared to have affected the profitability of the Domestic Industry during the POI as compared to the previous year. However, the profitability as compared to the base year has shown no significant adverse trend though there is a decline in profitability as compared to previous year. The authority agrees with the submissions made by the domestic industry that within the period of investigation, as a whole, evidence from the recent past provides the strongest indications of the likely future state of the domestic industry. After considering the trends, the authority notes that the domestic industry has suffered loss in profitability when compared with the previous year.

Profitability			
Year	Jan 00-Dec	Jan 01-Dec	Jan 02-Dec

Index	100.00	96.03	101.17
PBIT	****	****	****
Index	100.00	90.09	76.79
Return on capital employed	****	****	****
Index	100.00	93.81	75.91

(i) Ability to Raise Capital

45. The Authority has examined this parameter and proposes to conclude that it is not adversely affected by this parameter during the injury determination period.

(j) Employment and Wages

46. There has been a decline in manpower from 869 in 2000 to 784 during the period of investigation. However, it is not possible to draw any conclusion on account of this parameter as there are other products manufactured in the company and therefore, the Authority does not propose to conclude injury on account of this parameter.

Actual and Potential Negative Effects on Employment and Wages			
	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
No of Employees	****	****	****
% Change		-6.33	-3.69
Volume of sales/Employee	73.30	84.55	88.90

From the following table, it may also be seen that there is no decline in wages paid to the workers.

Year	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
Wages Total (Rs. Lacs)	****	****	****
Wages /employee (Rs.)	****	****	****

	00	01	02(POI)
Profit/loss per unit (Rs./MT)	****	****	****
Index	100.00	148.7	99.6
Net profit/loss (Rs. Lacs) after interest	****	****	****
Index	100.00	160.6	108.96

(g) Cash Flow

43. As the domestic industry is making uncoated papers also apart from the subject goods, the Authority could not cull out a separate cash flow for this subject goods during the injury period. However, as shown below, the domestic industry does not appear to have suffered any adverse trend on account of the cash profits during the injury period.

Cash profit			
	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
Cash profit Actual Lakhs	****	****	****
Index	100.00	120.98	111.56
Cash Profit/MT	****	****	****
Index	100	111.98	101.94

(h) Return on Investments

44. It may be seen from the following table that the return on investment has declined by almost 25% during the period of investigation as compared to the base year Jan-Dec 2000.

Capital Employed and ROI			
Year	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
Capital Employed	****	****	****

Index	100.00	115.16	125.35
Wages per unit of production(Rs./KG)	****	****	****
Index	100.00	107.87	113.09

(k) Productivity

47. The productivity per employee for the periods 2000, 2001 and 2002 is as under:

Productivity			
	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
Turnover Lakhs	****	****	****
Employees	869	814	784
Productivity %	****	****	****
Index	100.00	106.76	110.84

It is seen form the above table that the productivity of the Domestic Industry has increased. Hence, decline in productivity is not a factor causing injury to the domestic industry.

(m) Factors affecting domestic prices

48. The table below clearly shows that the prices from the subject countries have decreased from Rs. 38967 in 2000 to Rs. 34779 during the period of investigation.

	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
CIF Price of Dumped Imports (Rs/MT)	38967	33782	34779
Indexed	100.00	86.69	89.25

Domestic Prices (Rs./MT)	****	****	****
Indexed	100.00	97.63	96.01

It is noted from the table above that the import prices of subject goods from the subject countries are continuously coming at lower prices. It may be appreciated that the level of imports amongst other factors determines the domestic prices. The market prices in the domestic market may have been driven down by the higher volumes of dumped imports. However, the cost of the production of the domestic industry has also fallen significantly and has declined more than the decline in the sales price of the domestic industry. Further, while the import prices have increased during the POI as compared to the last year, the domestic selling prices have posted a decline with the cost of the production remaining almost same.

Year	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
Net sales Realization/MT	****	****	****
Trend	100.00	97.63	96.01

COP	****	****	****
Index	100	95.19	95.84

(n) Evidence of Lost Contracts

49. The domestic industry has claimed that it has lost sales orders on account of the dumped imports and they have attached some letters by the users as well as the importers in this regard. After examining the evidence, it is proposed to conclude that some sales orders may have been lost by the domestic industry though no loss of any significant contract has been noticed by the Authority.

(o) Magnitude of Margin of Dumping:

50. The margin of dumping ranges between 35-44% for Indonesia and 24-35% for European Union and is considered significant by the Authority..

(p) Growth

51. It may be noted that the overall market has shown 17.13% growth during the period of investigation as compared to the preceding year. The sales volume of the domestic industry has also increased during the period of investigation while the total sales revenue has come down. The growth of the domestic industry is negative in terms of market share (-11.8%) during the period of investigation as compared to previous year. At the same time the imports from the subject countries increased by around 8616 MT and the gain in market share of the low-priced dumped imports was as high as 17.03 percentage points in the period of investigation. However, there has not been any significant trend in the profitability of the firm during the injury period though profitability has declined during Period of Investigation as compared to previous year.

Actual and potential negative effects on Growth			
	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
Growth in Demand (%)		2.60	17.13
Growth in Sales Volume of Petitioner (%)		8.05	1.26
Growth in Turnover of Petitioner (%)		5.49	-0.42
Growth in Profit/MT (%)		48.70	-33.02

52 Conclusions of Injury:

With regard to volume effect of dumped imports, while the volume of dumped imports from subject countries increased significantly over the injury period in absolute and related terms, the domestic industry's sales volume increased only marginally showing a volume effect. However, the price effect on account of increase in the volumes of subject goods from subject countries has not been found present. The price undercutting while calculated cumulatively is significantly negative while the price underselling is considered insignificant. Though there is a little price depression in the selling prices of the domestic industry to the extent of 4% during the entire injury determination period, there is no price suppression during the same period as the cost of production has aligned with the decline in sales price during the same period. In fact, the authority holds that the prices of the dumped imports were significantly higher than those of the domestic industry during the period of investigation. With regard to impact on the domestic industry because of price and volume effects it is noted that the market share of the domestic

industry did show a decline in the injury determination period. However, this decline is understood to have been resulted due to increase in the demand of the subject goods in India and inability of the domestic industry to increase its capacity to cater to the increasing demand. Consequently, it could not be established that the decrease in market share held by the domestic industry was caused by the dumped imports. Further, while the import prices have increased during the POI as compared to the previous year, the domestic selling prices have posted a decline with the cost of production remaining almost the same. Though the profitability has declined during the POI as compared to the previous year, it has remained almost the same as compared to the base year. Though, the return on investment has declined during the POI as compared to previous years, this factor alone has not been considered sufficient to warrant a finding of material injury to the domestic industry. With regard to other parameters of injury as enumerated in the earlier paragraphs, the authority could not conclude injury on most of the parameters as mentioned in the Article 3.4 of the Anti-Dumping Agreement (ADA) such as production, capacity, capacity utilization, sales, employment, wages, productivity, cash profits, inventories as a percentage of sales, and inventories as a percentage of production. It is also noted by the authority that while the margin of dumping continues to be significant from the subject countries, there has not been any material impact or material injury on account of dumped imports from subject countries. Therefore, on the basis of the above, it is concluded that the domestic industry did not suffer a material injury during the period of investigation.

Threat of Injury and other factors

a. Significant Rate of Increase of Dumped Imports:

53. It may please be seen that the imports have increased from a level of 14084 MT during the year Jan-Dec 2000 to 33914 MT during the period of investigation. The year-to-year trend is given below:

b. Volume of imports from subject countries

Share of Imports from subject countries in Total imports			
	Jan 00- Dec 00	Jan 01- Dec 01	Jan 02- Dec 02(POI)
European Union (MT)	10027	15962	24323
Market Share	51.43%	73.32%	65.81%
Indonesia (MT)	4057	2750	9592
Market Share	20.81%	12.63%	25.95%

Total dumped Imports (MT)	14084	18712	33914
Total share of dumped imports from subject countries in total imports	72.24%	85.95%	91.77%

54. The Volume of the dumped imports has increased significantly from the subject countries as shown in the above table. In view of the fact the demand of the subject goods is increasing at a significant rate, the volume of imports from subject countries are likely to rise further given the fact that the domestic industry does not have the capacity to manufacture domestic like product at the level of the demand in the country.

Sufficient freely disposable capacity

55. The Authority has examined the submissions of the interested parties and has also verified the records of the few exporters. It is further noted that the domestic industry did not submit substantial information in their application before the Authority with regards to the parameters as enumerated in the 3.7 of the ADA. Subsequent to the initiation, the Authority received substantial information with respect to one exporter from EU and two from the Indonesia as other exporters from the EU did not cooperate. The Authority has ascertained from the data of the cooperating exporter that the EU exporter has significantly high capacity utilisation in the range of 90-98% while exporters from Indonesia have capacity utilisation of 74% to 95%. After examining the data from the only cooperating exporter from the EU, it is also noted that their exports to other countries have risen much more than exports to India during the injury period and the present volume of exports to India as compared to their total exports to other countries and their own domestic sales remain insignificant and is not expected to rise significantly.

d) Impact of Dumped Imports on Prices:

56. As regards the price effect, the following table shows the impact of dumped imports on the selling prices of the domestic industry:

Year	Domestic Price / MT
Jan 2000-Dec 2000	100
Jan 2001-Dec 2001	97.63

Jan 2002-Dec 2002

96.01

It is clear from the above table that the domestic industry has reduced its selling prices by Rs. 1741 /MT over the last two years. However, this reduction in the selling price has been accompanied by the corresponding reduction in the costs of the production of the domestic industry. Thus, the amount of price depression is not considered significant in this case considering the decline in the cost of production over the same period. Thus, in view of the evidence available, the price reduction is not considered imminent which may affect the profitability of the domestic industry.

Inventories of the Product Under Consideration:

57. As regards the inventories, it is considered that this parameter is not considered significant as the exporting producers especially from the EU have huge domestic sales and the exports to India is less than 1% of their total turnover. It is also verified that their landed price has been much higher than the domestic selling price of the domestic industry.

58. From the details of the imports given in the foregoing paragraphs, it is clear that the imports of subject goods from sources other than Indonesia and European Union are de minimis and/or is coming at higher prices during the period of investigation. Only the imports from Indonesia and European Union are being made at dumped prices and are above the de minimis limits. However, it is to be added that the import data from the subject countries has been significantly revised upwards in terms of volume and price after the data from the cooperating exporters has been made available to the Authority. After examining the data for the POI, it is seen that though the volume of imports have increased significantly during the injury determination period, they have not undercut the domestic industries price. In fact, the price undercutting from imports coming from EU is significantly negative and for all countries cumulated is also negative to the extent of -8% to -12%. There has been a marginal price underselling by the domestic industry when Non injurious price for the domestic industry is compared to the landed value from the subject countries cumulatively. The volume and value of imports from Non Subject countries is not significant.

59. Demand for subject goods is showing a steady growth. Decline in demand is hence not a factor causing injury to the domestic injury. It may also be seen that the market size is growing and therefore, contracting demand is not a factor for a possible injury to the Domestic Industry..

Effect of Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology, export performance or the productivity of the domestic industry or any other known factors.

60. There are no trade restrictive practices on the product under consideration. As regards the competition between the foreign and domestic producers, it is seen that the domestic and the imported products are competing in the same market and are used interchangeably. The export information of the domestic industry has been isolated for the purpose of this analysis and is dealt separately below.

Effect of other factors:

61. It is noted that no interested party has demonstrated that there are factors other than dumping from the subject countries which might be affecting the domestic prices or the performance of the domestic industry. However, several interested parties have submitted comments which have been analysed to the extent these have been considered relevant to the investigation.

1. Technology & Improvements:

62. In India, the subject goods are produced either through blade coating or air-knife technology. However, the petitioner is producing the subject goods only through the blade coating technology, which is the latest technology available to produce the coated paper. The imported goods are also produced from the blade coating technology and directly substitute the domestically produced coated paper by the petitioner.

2. Export Performance by the Domestic Industry:

63. The following table gives details about the export performance of the domestic industry. It may be seen that the exported volume has declined in the year 2001 as compared to year 2000. However, it has again risen substantially to a level of 27507 MT during the previous year. Thus, it is apparent that there is no trend in exports sales during the injury period.

Export performance

	Jan 00-Dec 00	Jan 01-Dec 01	Jan 02-Dec 02(POI)
MT	****	****	****
Indexed	100	41	85
Y/Y		-59%	106%
Trend			

64. Conclusions on Threat of Injury and Other factors

Subsequent to the issuance of disclosure statement, various interested parties have submitted comments on this parameter. The domestic industry has argued that the factors enumerated in 3.7 of the Agreement on Anti-Dumping needs to be analysed separately to gather an idea about the likely impact of the domestic industry because of dumped imports. However, the other interested parties have commented that there can either be an allegation of injury or allegation of threat of injury as the two are mutually exclusive. It has also been argued that the applicant has failed to submit sufficient information about the condition of the domestic industry in a threat of injury situation in order to demonstrate how the future imports are likely to cause the condition of the domestic industry to change. It was also added that the information relevant for a threat of injury case is substantially different from the information required for establishing material injury. It has further been added that in view of the failure of the applicant to provide the overall trends and projections affecting the likely conditions of, and the impact of imports on, the entire domestic industry including profit levels, market share, return on investment, capacity utilization, growth etc. and in view of the categorical statement made by BILT/BGPL in their own prospectus and financial statements regarding their own growth and lack of threat from imports, there is no reasonable basis for foreseeing any threat of injury to the domestic industry.

65. The authority has examined the contentions of various interested parties as mentioned above and also as per their submissions following the disclosure statement, it is noted that the applicant is bound to supply the most recent information on all injury parameters and other details to enable the authority to analyse the likely future impact in the threat of injury determination. However, the authority has examined all the parameters listed in 3.7 of the ADA to examine the impact of domestic industry from the threat of material injury. After the verification of the sole cooperating exporter from EU and Sinar Mas Group in Indonesia, it is held that these exporters do not have a very significant disposable capacity of the subject goods (the capacity utilization levels range about 90 to 97% levels in the EU while for Indonesia it ranges from 75% to 95%). It is also noted by the authority that their exports to other countries have risen much more than exports to India during the injury period as compared to previous year. With regard to dumped imports on prices, it has been held by the authority in the earlier paragraphs that the price effect in terms of price undercutting and price underselling are not considered as contributing to the injury to the domestic industry. Though there is a little price depression during the injury determination period, there is no price suppression. Thus, in view of the evidence available, the price reduction is not considered imminent which may affect the profitability of the domestic industry.

With regard to the inventories of the product under consideration, it is noted that these have not increased significantly during the injury determination period and are largely stable. With regard to examining the factors for the threat of material injury, it is stated that factors other than those set out in article 3.7 itself will necessarily be relevant to the determination of threat of material injury. It is further noted that an analysis of the consequent impact of the imports is required in a threat of material injury determination. The authority further notes that in making a determination regarding the threat of material injury, the investigating authority must conclude that material injury will occur in the absence of anti dumping duty. The authority notes that WTO Anti Dumping Agreement imposed a stringent conditions for the threat of injury determination such as the fact that such determinations must be based on facts not merely on allegation, conjecture or remote possibility and that change in circumstances which would create a situation in which dumping could cause injury must be clearly foreseen and imminent. The authority after examining all the arguments made by various interested parties does not conclude as to how the future will be different from the immediate past such that the situation of no present material injury will change in the imminent future to a situation of material injury in the absence of measures. Hence, in view of the above, the authority concludes that the domestic industry does not suffer from the threat of material injury because of the dumped imports from the subject countries.

Conclusions:

66. The Authority after considering the foregoing, concludes that

1. The subject goods have been imported from the subject countries below their normal value.
2. However, the domestic industry has not suffered material injury or threat of material injury.

67. Accordingly, the Authority does not recommend imposition of anti dumping duties on imports of subject goods from subject countries.

DR. CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority